मनदीप कौर, डायरेक्टर

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ

राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र

आज तक आमने-सामने

दिल्ली,पंजाब,हरियाणा,हिमाचल प्रदेश,जम्मू कश्मीर | मुल्य : 5 रुपए

Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com
RNI No-Punhin2013/54688 1-15 March 2026

एस. के. सक्सैना, मुख्य संपादक

साल 2026 /संपादक एसके सक्सैना / www aajtakaamnesaamne.com /Help Line 9878552070

जहां कांग्रेस सोचना बंद कर देती है हम काम करना शुरू कर देते हैं-मोदी

कहा– सरकार लोगों के लिए काम कर रही

नई दिल्ली, एजंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार वैश्विक संघर्षों के कारण लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस देश में दहशत पैदा करने की कोशिश करके %%गैर–जिम्मेदाराना%% व्यवहार कर रही है। मोदी ने असम के सिलचर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर की अनदेखी की और स्वतंत्रता के दौरान ऐसी सीमा रेखा खींचने की अनुमति दी जिससे समुद्री मार्ग से बराक घाटी का संपर्क टूट गया। उन्होंने कहा, विश्व में जारी युद्धों को देखते हुए, हमारा प्रयास है कि देश की जनता पर इनका प्रभाव कम से कम हो। कांग्रेस को एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभानी चाहिए थी लेकिन वह ऐसा करने में विफल रही। वह जनता में दहशत फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, उसके (कांग्रेस) पास न तो असम के लिए कोई दूरदृष्टि है और न ही राष्ट्र के लिए; वे (कांग्रेस नेता) केवल मोदी को गाली देना, अफवाहें फैलाना और लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोलना जानते हैं। मोदी ने कहा कि बराक घाटी कभी व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को जिस तरह उसके हाल पर छोड़ दिया, उसने उसी तरह बराक घाटी को कमजोर करने में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, %%बराक घाटी, जो कभी औद्योगिक केंद्र के रूप में जानी जाती थी, अपनी मूल ताकत खो बैठी। आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस सरकारें सत्ता में रहीं, फिर भी इस क्षेत्र में विकास न के बराबर हुआ। आज भाजपा सरकार इसे बदलने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राज्य के युवाओं को हिंसा और उग्रवाद के रास्ते पर धकेल दिया, जबकि भाजपा ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य उनके लिए अवसरों का सागर बन जाए। उन्होंने कहा, जहां कांग्रेस सोचना बंद कर देती है, हम काम करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का मूलमंत्र विकास में पिछड़े लोगों को प्राथमिकता देना है।

पंजाब 10 हजार करोड़ निवेश करेगा उद्योग जगत–भगवंत मान

शिखर सम्मेलन में मान सरकार ने दिग्गज कारोबारियों के लिए बिछाए पलक पांवड़े

एस. के. सक्सैना

मोहाली, प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन–2026 की शुक्रवार को मोहाली में धमाकेदार शुरुआत हुई। सम्मेलन के पहले दिन ही बड़ी औद्योगिक कंपनियों ने राज्य में कुल 10,000 करोड़ रुपये निवेश करने का वादा किया। आर्सेलर मित्तल, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, टाटा स्टील्स और ट्राइडेंट ग्रुप समेत कई दिग्गज उद्योगपतियों ने पंजाब की नयी औद्योगिक और व्यापार विकास नीति का समर्थन करते हुए अपने परिचालन का विस्तार करने की योजना का ऐलान किया।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उद्योगपतियों का स्वागत करते हुए कहा कि हम एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं जो विकास को गति देगा। हमारी नीति मांग आधारित है और सभी औद्योगिक क्षेत्रों को कवर करती है। उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब उच्च तकनीक वाले औद्योगीकरण और सतत विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही 15 प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होगी। शिखर सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मुख्य अतिथि थे। ब्रिटेन, जापान और कोरिया की कंपनियों ने भी निवेश योजनाओं की घोषणा की। ब्रिटेन की 3 एसोसिएट्स ने 1,407 करोड़ रुपये और जापानी कंपनी टॉपपन स्पेशलिटी फिल्म्स ने 300–400 करोड़ रुपये निवेश की योजना रखी। 2,600 करोड़ का अतिरिक्त निवेश ः वैश्विक इस्पात कंपनी आर्सेलरमित्तल के कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मी एन मित्तल ने गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी में 2,600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे फार्मा और रसायन क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे। कंपनी हरित ऊर्जा में भी निवेश बढ़ाएगी और बठिंडा में एआई संचालित 500 खुदरा ईंधन आउटलेट खोलेगी। टाटा स्टील्स की 3200 करोड़ निवेश की घोषणा ः टाटा स्टील्स ने लुधियाना में विशेष इस्पात निर्माण इकाई स्थापित करने और 3,200 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना की घोषणा की। सीईओ टी वी नरेंद्रन ने कहा कि यह परियोजना दो साल के भीतर चालू होगी और उनका ध्यान हरित इस्पात उत्पादन पर रहेगा। ट्राइडेंट ग्रुप 5,000 महिलाओं को देगा नौकरियां ः ट्राइडेंट ग्रुप अगले दो वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश कर 10,000 नौकरियां सृजित करेगा, जिनमें से 5,000 नौकरियां महिलाओं के लिए होंगी।

अब और 'छोटा भाई' नहीं, पंजाब में अकेले लड़ेंगे चुनाव : शाह

भाजपा ने मोगा में फूंका विधानसभा चुनाव का बिगुल

मनदीप कौर

मोगा,पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का चुनावी बिगुल फूंकते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरोमणि अकाली दल बादल के साथ संभावित गठबंधन की अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा अब छोटे भाई की भूमिका निभाते–निभाते थक चुकी है और राज्य में सरकार बनाने के लिए वह अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। शाह शनिवार को मोगा जिले के किली चाहलान गांव में पार्टी की 'बदलाव रैली' को संबोधित कर रहे थे। मंच पर केसरिया पगड़ी पहनकर पहुंचे शाह ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब में डबल–इंजन सरकार व बदलाव लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी (आप) का शासन पहले ही देख चुकी है। उन्होंने कानून–व्यवस्था, नशे की समस्या, धर्मांतरण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर पंजाब की भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के लिए एक एटीएम बन गई है। उन्होंने लोगों से कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक मौका दें, जिससे राज्य में बदलाव लाया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि कोई पंजाब को नशे और अन्य समस्याओं से मुक्त कर सकता है, तो वह केवल नरेंद्र मोदी और भाजपा ही हैं। शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री मान को शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली के चार 'सूबेदार' राज्य में बैठे हुए हैं और यहां की सारी संपत्ति बाहर भेज रहे हैं। शाह ने कहा कि भाजपा को एक मौका दें, हम पंजाब में बदलाव लाएंगे। शाह ने कहा की मान सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि 2026 में तीन गांवों के सरपंच मारे गए, जबकि गैंगस्टर लोगों से पैसे उगाह रहे हैं। भारत–अमेरिका व्यापार समझौते पर, शाह ने 'आप' सरकार और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। शाह ने वादा किया कि यदि भाजपा 2027 में सत्ता में आई तो नशे का धंधा सिर्फ दो साल में जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। शाह ने कहा, 'इस राज्य में कोई सरकार नहीं है। अगर कोई सरकार होती, तो कानून–व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब नहीं होती; राज्य नशे की समस्या से जूझता नहीं और किसान इतनी पीड़ा में नहीं होतेज मान केवल केजरीवाल के पायलट के रूप में

कांग्रेस ने चाबहार बंदरगाह को लेकर की सरकार की आलोचना, कहा- कूटनीति को लगा दूसरा रणनीतिक झटका

चाबहार बंदरगाह में निवेश की संभावनाएं तलाशना शुरू किया था

नई दिल्ली, एजंसी

कांग्रेस ने रविवार को कहा कि चाबहार बंदरगाह अब भारत की प्राथमिकताओं में दिखाई नहीं दे रहा और यह ताजिकिस्तान के आयनी में वायुसेना अड्डा बंद होने के बाद देश की कूटनीति को लगा दूसरा %%रणनीतिक झटका%% है। कांग्रेस के महासचिव एवं संचार प्रभारी जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि शासन में निरंतरता एक ऐसी जरूरी हकीकत है, जिसे आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री कभी स्वीकार नहीं करते। रमेश ने %एक्स% पर कहा कि 1990 के दशक के आखिर में भारत ने भारत–अफगानिस्तान–ईरान सहयोग रणनीति के तहत ईरान के चाबहार बंदरगाह में निवेश की संभावनाएं तलाशना शुरू किया था। उन्होंने कहा कि आखिरकार, तेहरान में 16वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद डॉ. मनमोहन सिंह ने इन योजनाओं को नया प्रोत्साहन दिया था। मई 2013 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुरुआत में चाबहार में 11 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर के निवेश को मंजूरी दी। यह याद रखना चाहिए कि यह फैसला उस समय लिया गया था, जब भारत अक्टूबर 2008 में हस्ताक्षरित भारत–अमेरिका परमाणु समझौते को लागू करने के लिए बड़े कदम उठा रहा था। उन्होंने कहा कि इसके बाद अक्टूबर 2014 में मोदी सरकार ने, जैसा कि वह हमेशा करती रही है, डॉ. सिंह की चाबहार पहल को नए तरीके से पेश कर उसे प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण का हिस्सा बताया। कांग्रेस नेता ने कहा, %%2026–27 के बजट में चाबहार के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया। क्या इसका मतलब यह है कि भारत इससे बाहर हो गया है या फिर फिलहाल उसकी निवेश संबंधी प्रतिबद्धताएं पूरी हो चुकी हैं? रमेश ने कहा कि इसका मतलब है कि चीन द्वारा निर्मित पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से करीब 170 किलोमीटर पश्चिम में स्थित चाबहार अब भारत की प्राथमिकताओं में नहीं दिख रहा। यह ताजिकिस्तान में दुशांबे के पास आयनी में भारत के वायुसेना अड्डे को बंद किए जाने के बाद भारत की मध्य एशियाई कूटनीति को लगा दूसरा रणनीतिक झटका है। भारत ने अतीत से अलग रुख अपनाते हुए अपने केंद्रीय बजट में चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई धन आवंटित नहीं किया है।

लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की नजरबंदी समाप्त

नई दिल्ली, एजंसी

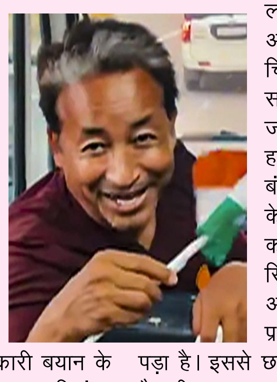

केंद्र सरकार ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक की नजरबंदी को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने तथा सभी हितधारकों के साथ सार्थक संवाद को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। सरकारी बयान के अनुसार, लेह में 24 सितंबर 2025 को उत्पन्न हुई कानून–व्यवस्था की गंभीर स्थिति के बाद 26 सितंबर 2025 को जिला मजिस्ट्रेट, लेह के आदेश पर NSA के तहत सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया था। सरकार ने कहा कि वह इस अधिनियम के तहत निर्धारित हिरासत अवधि का लगभग आधा समय पूरा कर चुके हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि सरकार लद्दाख के विभिन्न समुदायों और हितधारकों के साथ लगातार संवाद कर रही है ताकि क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं और चिंताओं का समाधान किया जा सके। हालांकि, लगातार बंद और प्रदर्शनों के कारण क्षेत्र की सामान्य स्थिति और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इससे छात्रों, नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं, व्यापारियों, पर्यटन से जुड़े लोगों और पर्यटकों पर भी प्रभाव पड़ा है। सरकार ने कहा कि लद्दाख में शांति और स्थिरता का वातावरण बनाना प्राथमिकता है, ताकि सभी पक्षों के साथ रचनात्मक बातचीत संभव हो सके।

राहुल गांधी का हमला, बोले–सरकार अपने स्वार्थ के लिए कृषि कुर्बान करने को तैयार

कहा, संसद के भीतर और बाहर आवाज़ उठाते रहेंगे

नई दिल्ली, एजंसी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में अपने एक लिखित प्रश्न और सरकार के जवाब का हवाला देते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि सरकार अपने स्वार्थ के लिए भारतीय कृषि को कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी कहा कि वह किसानों के अधिकार और MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की रक्षा के लिए संसद के भीतर और बाहर आवाज़ उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने अपने अतारांकित प्रश्न और सरकार के उत्तर की प्रति साझा करते हुए फेसबुक पर लिखा, ऽलोकसभा में मैंने सरकार से सीधा सवाल पूछा था कि 2021 में किसानों से किया गया सी2+50 प्रतिशत कानूनी रूस्क्र का वादा अब तक लागू क्यों नहीं हुआ? सरकार ने जवाब देने से बचते हुए सिर्फ अपनी पुरानी रूस्क्र की नीति दोहरा दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि उसने राज्यों पर रूस्क्र बोनस खत्म करने का दबाव डाला और उसने इसे बिना किसी तर्क के ऽराष्ट्रीय प्राथमिकताओंऽ के नाम पर सही ठहराया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ऽएक और गंभीर सवाल यह है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में ऽगैर व्यापारिक अवरोधऽ घटाने की बात कही गई है। क्या इसका मतलब रूस्क्र और सरकारी खरीद को कमजोर करना है? सरकार इस सवाल से भी बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों से किया वादा निभाना नहीं चाहती और वह %%अपने स्वार्थ के लिए भारतीय कृषि को कुर्बान करने को भी तैयार%% है। राहुल गांधी ने कहा, ऽहम किसानों के अधिकार और रूस्क्र की रक्षा के लिए संसद के भीतर और बाहर आवाज उठाते रहेंगे। रायबरेली से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने 10 मार्च को लिखित प्रश्न किया था कि क्या सरकार ने 2021 में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से वादा किया था कि वह सभी फसलों के लिए ऽसी2+50 प्रतिशत ऽ की दर से विधिक गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य (रूस्क्र) लागू करने पर विचार करेगी? इसके उत्तर में कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा, ऽप्रत्येक वर्ष, सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सुझावों पर विचार करने के बाद कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (ष्टक्रष्टक्क) की सिफारिशों के आधार पर पूरे देश में 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (रूस्क्र) निर्धारित करती है। मंत्री ने यह भी कहा था कि वर्ष 2018–19 के केंद्रीय बजट में रूस्क्र को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के लिए पूर्व–निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। उन्होंने, ऽइसी के अनुसार, सरकार ने वर्ष 2018–19 से उत्पादन की औसत लागत पर 50 प्रतिशत के न्यूनतम रिटर्न के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए रूस्क्र में वृद्धि की थी, जिससे देश भर के किसान लाभान्वित हुए हैं।

आर्थिक स्थिरीकरण कोष से वैश्विक चुनौतियों से निपटेगी सरकार-निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली, एजंसी

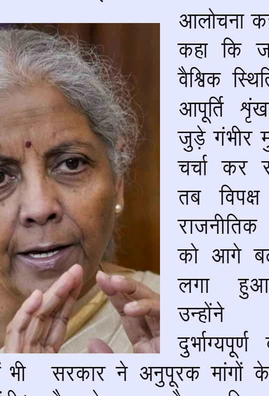

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि एक लाख करोड़ रुपये का आर्थिक स्थिरीकरण कोष (इकोनॉमिक स्टेबिलाइज़ेशन फंड) देश को वैश्विक संकटों से उत्पन्न आर्थिक झटकों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह कोष सरकार के लिए एक %बफर% की तरह काम करेगा, जिससे पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्रों में उत्पन्न संकट या वैश्विक आपूर्ति शृंखला में बाधा आने की स्थिति में भी सरकारी योजनाएं प्रभावित नहीं होंगी। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि यह कोष भारत की वित्तीय मजबूती को बढ़ाएगा और आकस्मिक वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से देश आर्थिक अस्थिरता के दौर में भी योजनाओं को पटरी से उतारे बिना आगे बढ़ सकेगा। चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा पश्चिम एशिया संकट और एलपीजी की कथित कमी को लेकर हंगामा किया गया। इस पर सीतारमण ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि जब वह वैश्विक स्थिति और आपूर्ति शृंखला से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर रही हैं, तब विपक्ष अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सरकार ने अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच के तहत मौजूदा वित्त वर्ष में 2.81 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त सकल व्यय के लिए लोकसभा से मंजूरी मांगी थी। इसमें 80,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्तियों को शामिल करते हुए कुल अतिरिक्त नकद व्यय लगभग 2.01 लाख करोड़ रुपये होगा।

पंजाब इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर हब के रूप में उत्तर भारत में उभरने लगा

पंजाब में भविष्य का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मौजूद; पी.डी.सी. चेयरपर्सन सीमा बंसल ने देशी और विदेशी ईएसडीएम कंपनियों को पंजाब के साथ साझेदारी का निमंत्रण दिया

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़/एस.ए.एस. नगर, 14 मार्च–प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026 के दूसरे दिन राज्य में निवेश के अवसरों को उजागर करते हुए प्लाक्शा यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) से संबंधित आयोजित सत्र में पंजाब में निवेश करने के फायदों पर प्रकाश डाला गया। पंजाब की नई औद्योगिक नीति के बारे में जानकारी देते हुए पंजाब डेवलपमेंट कमीशन की चेयरपर्सन सीमा बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें ईएसडीएम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि नीतिगत प्रोत्साहनों के अलावा पंजाब में अनुकूल व्यापारिक माहौल, उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थान, कुशल मानव संसाधन और मजबूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। सीमा बंसल ने आगे कहा कि पंजाब विश्व स्तरीय औद्योगिक ढांचा उपलब्ध कराकर, उद्योग और अकादमिक संस्थानों के बीच साझेदारी को मजबूत कर और अनुसंधान, डिजाइन तथा नवाचार को प्रोत्साहित करके एक मजबूत ईएसडीएम इकोसिस्टम तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। टॉपन स्पेशियलिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के अविनाश सिंह ने पंजाब में कारोबार करने के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पंजाब सरकार उद्योगों को समर्थन देने में काफी सक्रिय रही है और राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करते समय उनकी कंपनी को अपेक्षा से अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुए। इस दौरान एच.सी.एल. टेक्नोलॉजी के कमलजीत सिंह ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बड़ी मांग है, जो ईएसडीएम उद्योग में बड़े विकास की संभावना दर्शाती है। उन्होंने कहा कि कुशल मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और व्यापार–समर्थक नीतियों के कारण पंजाब निवेश के लिए एक आदर्श स्थान है। अन्य वक्ता सी.डी.आई.एल. सेमीकंडक्टर्स के पृथ्वीदीप सिंह ने कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में मोहाली भारत के प्रमुख तकनीकी केंद्रों जैसे बेंगलुरु, अहमदाबाद और जयपुर के साथ मजबूती से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। उन्होंने कहा कि आकर्षक नीतियां, गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति और सक्षम मानव संसाधन की उपलब्धता पंजाब में निवेश को आकर्षित करने के प्रमुख कारक हैं। इसके अलावा इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के धर्मेंद्र सिंह यादव ने भी पंजाब को निवेश के लिए एक आदर्श स्थान बताया। इस सत्र का संचालन बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अंकुश वाडेरा द्वारा किया गया।

प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट-2026 : पंजाब युवाओं के मन में नौकरी देने वाले पैदा करने के लिए उद्यमिता बो रहा है-हरजोत बैंस

कहा! मान सरकार शिक्षा संस्थानों को पावरहाउस में बदल रही है

कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा

चंडीगढ़, कुशल मानव पूंजी के लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में पंजाब की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में, पंजाब के शिक्षा मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस ने भविष्य में राज्य की शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, जिसका उद्देश्य पंजाब को प्रतिभा, नवाचार और उद्यमिता के पावरहाउस में बदलना है। प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट–2026 में 卐ज्ञान से पूंजी तक- यूनिवर्सिटीज़ को प्रतिभा, नवाचार और उद्यमिता इंजन में बदलना卐 सत्र के दौरान दर्शकों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए, सरदार हरजोत सिंह बैंस ने जोर देकर कहा कि राज्य की शिक्षा प्रणाली एक पैराडाइम शिफ्ट से गुजर रही है, जो सिर्फ पहुंच से आगे है। पिछले चार वर्षों से, शिक्षा मंत्री के रूप में सेवा निभाना सीखने के उद्देश्य को फिर से परिभाषित करने का मिशन रहा है। उन्होंने पंजाब के कल के उद्योगों के निर्माण पर जोर दिया क्योंकि पंजाब अब सिर्फ अवसरों की धरती नहीं है। यह इसका इंजन बन रहा है। कैबिनेट मंत्री ने उद्यमिता मानसिकता कोर्स (ई.एम.सी.) की सफलता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सितंबर 2025 से, 1 लाख से अधिक छात्रों ने वास्तविक व्यवसाय बनाए हैं, जिससे 66 करोड़ रुपए का सामूहिक राजस्व उत्पन्न हुआ है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय पंजाब को ई.एम.सी. शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने, छात्रों को व्यावहारिक उद्यमिता अनुभव देने को दिया। उद्यमिता को राज्य का भविष्य बताते हुए, सरदार हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि 2025–26 से उच्च शिक्षा में उद्यमिता एक अनिवार्य विषय है, जिसकी शुरुआत बी.बी.ए., बी.कॉम, बी.टेक और बी.वोक कोर्सों से होगी। राज्य %हुनर शिक्षा स्कूल% और बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम की सफलता को उजागर करते हुए, व्यवसाय, लीडरशिप और समस्या समाधान जैसे व्यावहारिक कौशलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। शिक्षा मंत्री ने मेडिकल शिक्षा की समानताओं को उजागर करते हुए, एक 卐फ्लिप्ड क्लासरूम卐 मॉडल की कल्पना की। उन्होंने कहा 卐दो घंटे थ्योरी, बाकी समय अस्पताल में वास्तविक जीवन की इमरजेंसी का सामना करना – यही टेम्पलेट है,卐 उन्होंने जोर देकर कहा कि इंजीनियरिंग और अन्य धाराओं के छात्रों को कैंपस में दो सप्ताह बिताने और बाकी उद्योग में, सीखते हुए कमाई करने की वकालत करते हुए कहा यही भविष्य है जो हम बना रहे हैं। निवेशकों को सबसे अच्छा निवेश करने का आह्वान करते हुए, कैबिनेट मंत्री बैंस ने राष्ट्रीय रैंकिंग में पंजाब की तेजी से बढ़ोतरी का प्रदर्शन किया, जिससे पराख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में राज्य के शीर्ष स्थान को उजागर किया गया। पंजाब एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्य विदेशी छात्रों की बड़ी संख्या में दूसरे स्थान पर भी है और आईआईटी रोपड़, आईआईएसईआर, एमिटी, आईआईएम अमृतसर और एम्स बठिंडा जैसे विश्व स्तरीय संस्थानों का गौरव करता है।

उन्होंने बेमानी तकनीक के उपयोग के खिलाफ भी चेतावनी दी, सवाल किया कि क्या दिमाग बहुत ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, हमें तकनीक के साथ सीखना चाहिए, इससे अपंग नहीं होना चाहिए।

प्रशासकीय सचिव स्कूल और उच्च शिक्षा श्रीमती सोनाली गिरी ने जोर देकर कहा कि पंजाब शिक्षा को सिर्फ पहुंच से आगे महत्व देता है, प्रासंगिकता और उद्योग की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि %हुनर शिक्षा स्कूल% और %पंजाब स्टार्टअप ऐप% जैसी पहलों को उजागर किया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षा और उद्योग को जोड़ने वाला एक सहयोगी इकोसिस्टम बनाना है। राज्य एक सहज इकोसिस्टम बना रहा है जहां प्रतिभा को एक संस्कृति को उत्साहित करने के लिए अवसर मिलते हैं जहां छात्र फल–फूल सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में 40 यूनिवर्सिटी, 1,000 से अधिक कॉलेज और उच्च शिक्षा में 7 लाख छात्र हैं, जो इसे प्रतिभा और नवाचार का केंद्र बनाते हैं।

हुनर पोर्टल के पहले चरण की शुरुआत, छात्रों को नौकरी पर प्रशिक्षण और नौकरियों के लिए उद्योग से जोड़ना, एक बड़ा मील का पत्थर है। तकनीकी शिक्षा के निदेशक श्री मोनीष कुमार ने कहा कि यह पोर्टल खाई को पूरा करता है, खासकर आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए।

टैटर कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड मास्टर्स यूनियन के संस्थापक और शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 के जज, प्रथम मित्तल, जिन्होंने ईएमसी डिजाइन किया, ने पंजाब के साहसिक कदम की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार की पहल परिवर्तनकारी है। छात्र वास्तविक व्यवसाय बना रहे हैं, उत्पाद बेच रहे हैं और राजस्व उत्पन्न कर रहे हैं – यही भविष्य है।

चर्चा ने यह भी उजागर किया कि यह मानसिकता जल्द शुरू होती है। बेडफोर्ड यूके स्कूल मोहाली की संस्थापक प्रिंसिपल श्रीमती नाओमी एटकिंस ने नोट किया कि लचीलापन और रचनात्मक समस्या–समाधान जैसे कौशल खेल–आधारित प्रशिक्षण में शुरू होते हैं। पंजाब इस सोच को जल्द बोने का हकदार है।

इसे प्लाक्षा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. रुद्र प्रताप की सूझों द्वारा पूरक किया गया था, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूनिवर्सिटीज़ को अब छात्रों को जटिल समस्या–समाधान के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए, न कि पाठ–पुस्तकों की याददाश्त के लिए। प्लाक्षा का पाठ्यक्रम पंजाब द्वारा अपनाए जा रहे उद्यमी दृष्टिकोण का प्रमाण है।

एआई के उपयोग से सरकारी सेवाओं को तेज और प्रभावी बनाएगी पंजाब सरकार-संजीव अरोड़ा

पंकज

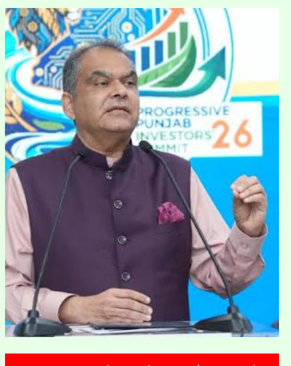

कहा, राज्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सदुपयोग से युवा सशक्तिकरण, कृषि, उद्योग और प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध

चंडीगढ़ / एस.ए.एस. नगर, प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के दूसरे दिन उस समय खास पल देखने को मिले, जब उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) की क्रांति को अपनाने के लिए विस्तृत योजनाओं की घोषणा की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर आयोजित समापन सैशन के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रयास करेगी कि पंजाब, विशेषकर यहां के युवा, तेजी से आगे बढ़ रही एआई तकनीक का पूरा लाभ उठा सकें। प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मंत्री अरोड़ा ने बताया कि राज्य सरकार योजनाबद्ध तरीके से अपने सभी विभागों में एआई के उपयोग की ओर कदम बढ़ाएगी। उन्होंने कहा, इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज करना और लोगों तक सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आसानी से पहुँचाने योग बनाना है। बड़ी संख्या में उपस्थित उद्योगपतियों और निवेशकों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने तकनीक के बढ़ते व्यापक उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 卐एआई अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और यह जरूरी है कि हम इसका सही और जिम्मेदार तरीके से उपयोग करें। सम्मेलन को मिले उत्साहजनक समर्थन पर संतोष व्यक्त करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि आज दिनभर हुए 26 सैशनों की भागीदारी और प्रतिक्रिया पंजाब के विकास की यात्रा में निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है। इस सैशन में तकनीक, अकादमिक और उद्योग क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों की भागीदारी के साथ एक महत्वपूर्ण पैनल चर्चा भी हुई। पैनल में ङ्गस्स्थ्हह्ल की को–फाउंडर कोमल तलवार, गंगा एक्रोवल के अमित थापर, प्लाक्षा यूनिवर्सिटी के प्रो. राजीव रतन शाह और एसटीपीआई मोहाली के डायरेक्टर शैलेन्द्र त्यागी शामिल थे। चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि प्राइवेट क्षेत्र में एआई की परिवर्तनकारी क्षमता बहुत बड़ी है और इसके उपयोग से किसी कंपनी की उत्पादकता में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो सकती है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि उद्योगों को सबसे पहले अपनी व्यावसायिक समस्याओं की पहचान करनी चाहिए और फिर रणनीतिक तरीके से एआई की मदद से उनका समाधान खोजना चाहिए। कॉरपोरेट कार्यकुशलता के अलावा विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि एआई पंजाब के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग और व्यापार में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है और राज्य के प्रशासन को और बेहतर बना सकती है। अनुकूल नवाचार वातावरण तैयार करने पर जोर देते हुए विशेषज्ञों ने सरकार को सुझाव दिया कि शुरुआती स्तर के एआई स्टार्टअप्स को समर्थन दिया जाए और उन्हें सब्सिडी वाली क्लाउड स्टोरेज तथा मजबूत डेटा बेस ढांचा उपलब्ध कराया जाए।

फार्मा और बायोटैक : पंजाब फार्मास्यूटिकल निर्माण के लिए प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर रहा है - स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह

रमन कुमार

कैबिनेट मंत्री ने खोज और विकास पर जोर दिया, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार से पूर्ण समर्थन देने का भी दिया भरोसा

चंडीगढ़/मोहाली, पंजाब को फार्मास्यूटिकल निर्माण के लिए सर्वोत्तम स्थान बताते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मैडिकल शिक्षा एवं खोज मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने निवेशकों और उद्योगपतियों को राज्य में अपने उद्यम स्थापित करने का निमंत्रण दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार से पूर्ण समर्थन देने का भी भरोसा दिया। प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026 के दूसरे दिन %फार्मास्यूटिकल निर्माण के लिए पंजाब की स्थिति% विषय पर 卐फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी卐 शीर्षक वाले सैशन को संबोधित करते हुए, स्वास्थ्य मंत्री ने उद्योग के नेताओं से सीधे बातचीत की और उनसे पूछा कि निवेश करने के लिए उन्हें क्या आवश्यकताएं हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब के पास एक समृद्ध फार्मा हब के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं, जिसमें मजबूत बुनियादी ढांचा, उच्च स्तरीय मेडिकल और फार्मास्यूटिकल संस्थान तथा उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और खोज एवं विकास के लिए प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर) शामिल हैं। नवाचार की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देते हुए, डॉ. बलबीर सिंह ने वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए खोज और विकास की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आसान मंजूरियां और कारोबार–अनुकूल वातावरण प्रदान करके उद्योग को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, 卐मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की गतिशील अगुवाई के तहत पंजाब सरकार फार्मा उद्योग को बेमिसाल सहायता प्रदान कर रही है। हमारे पास एनआईपीईआर से प्रतिभा है, हमारे पास बुनियादी ढांचा है और अब हमारे पास इसे कारोबार करने के लिए सबसे आसान जगह बनाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति है।卐 उन्होंने निवेशकों से अपील की कि वे पंजाब को अपनी पसंदीदा गंतव्य मानें। राज्य के रणनीतिक लाभों और नए उद्योगों को संभालने में सरकार की सक्रिय दृष्टिकोण को उजागर करते हुए कैबिनेट मंत्री ने पंजाब सरकार द्वारा लाई जा रही नई औद्योगिक नीति की एक झलक भी दी, जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन और एक सुचारू रेगुलेटरी ढांचा पेश करने के लिए तैयार की गई है। सैशन में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमार राहुल, इंड–स्विफ्ट ग्रुप के सीएमडी एनआर मुंजाल, सीएमडी टाइनॉर पीजे सिंह, डा रखना एनआईपीईआर दुलाल पांडा, सनफार्मा में कॉर्पोरेट रिलेशंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एएच खान सहित प्रमुख पैनलिस्ट शामिल थे, जबकि केपीएमजी से रमेश शनमुगम सैशन का संचालन कर रहे थे।

संपादकीय

ऊर्जा सुरक्षा

21वीं सदी की दुनिया की राजनीति में, एनर्जी रिसोर्स न सिर्फ़ आर्थिक विकास का आधार हैं, बल्कि स्ट्रेटेजिक पावर, डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिकल झगड़ों का भी केंद्र बन गए हैं। पश्चिम एशिया, खासकर मिडिल ईस्ट इलाका, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स की धुरी रहा है। अभी, ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच बढ़ता मिलिट्री तनाव एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच गया है जहाँ इसका असर सिर्फ़ इलाके की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी, व्यापार और आर्थिक स्थिरता पर पड़ रहा है। इस बैकग्राउंड में, दुनिया का सबसे ज़रूरी समुद्री एनर्जी रूट, होर्मुज की खाड़ी, दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बन गई है। इस खाड़ी को दुनिया भर के तेल व्यापार की लाइफलाइन माना जाता है। वहाँ होने वाली कोई भी अस्थिरता का तुरंत असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हाल के दिनों में, इस रास्ते से गुज़रने वाले जहाजों पर हमले, ड्रोन हमले और संभावित माइन बिछाने की खबरों ने इंटरनेशनल मार्केट को अस्थिर कर दिया है। मैं मानता हूँ कि इसी वजह से भारत समेत कई देशों ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा मतलब कि एनर्जी सिक्योरिटी सतर्कता बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को भारत सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है, और इसकी एनर्जी ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा वेस्ट एशिया से आता है। ऐसे में, सप्लाई में कोई भी रुकावट सीधे तौर पर भारत की इकॉनमी और आम लोगों की ज़िंदगी पर असर डाल सकती है। इस संभावित खतरे को देखते हुए, भारत सरकार ने हाई–लेवल तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने हालात पर नज़र रखने और संभावित संकटों को हल करने के लिए गृह मंत्री की अगुवाई में तीन सदस्यों का ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स बनाया है। इस कमेटी में विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री भी शामिल हैं। यह कमेटी अलग–अलग मंत्रालयों और एनर्जी कंपनियों के साथ मिलकर लगातार हालात का रिव्यू कर रही है। सरकार का मकसद यह पक्का करना है कि देश में पेट्रोल, डीज़ल, गैस और स्क्क्र की सप्लाई किसी भी हालत में बिना रुके बनी रहे। प्रधानमंत्री ऑफिस ने भी सभी संबंधित डिपार्टमेंट को इस मुद्दे पर कोऑर्डिनेट करने और एक मज़बूत सप्लाई चेन बनाए रखने का निर्देश दिया है। दोस्तों, अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी और घरेलू सप्लाई पर विचार करें,. सरकार की प्राथमिकता, तो तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी के साथ भारत की एनर्जी ज़रूरतें लगातार बढ़ रही हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, खेती और घरेलू इस्तेमाल समेत सभी सेक्टर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसलिए, सरकार भारतीय कंज्यूमर्स पर इंटरनेशनल संकट के असर को कम से कम करने की कोशिश कर रही है। तेल कंपनियों को सही स्टोरेज बनाए रखने और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, घरेलू स्क्क्र सिलेंडर की सप्लाई को प्राथमिकता देने के लिए खास इंतज़ाम किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ इलाकों में कुछ समय के लिए स्क्क्र की कमी की खबरें आई हैं, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि यह कोई बड़ा संकट नहीं है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़ा एक लोकल मामला है। सरकार ने पूरे देश में स्क्क्र की उपलब्धता पर लगातार नज़र रखने के लिए एक खास कंट्रोल रूम भी बनाया है। यह कदम दिखाता है कि भारत सरकार किसी भी संभावित संकट के लिए तैयार रहने का इरादा रखती है। दोस्तों, अगर हम होर्मुज जलडमरूमध्य को ग्लोबल एनर्जी ट्रेड का हब मानते हैं, तो होर्मुज जलडमरूमध्य को दुनिया के एनर्जी मैप में सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक महत्व का माना जाता है। यह जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और खाड़ी देशों से दुनिया के अलग–अलग हिस्सों में तेल और गैस पहुंचाता है। ज्योग्राफिकली, यह स्ट्रेट उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच है। इसके एंट्री और एग्जिट पर इसकी चौड़ाई लगभग 50 ऋद्व है, जबकि अपने सबसे पतले पॉइंट पर यह सिकुड़कर लगभग 33 ऋद्व रह जाती है। इसके बावजूद, यह इतनी गहरी है कि दुनिया के सबसे बड़े ऑयल टैंकर भी इससे गुज़र सकते हैं। हर महीने 3,000 से ज़्यादा जहाज़ इस स्ट्रेट से गुज़रते हैं, और दुनिया की लगभग 30 परसेंट ऑयल सप्लाई यहीं से गुज़रती है। इसीलिए इसे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए चोकपॉइंट कहा जाता है। इस रास्ते में कोई भी रुकावट तुरंत तेल की कीमतों पर असर डालती है। दोस्तों, अगर हम समुद्री हमलों और ग्लोबल चिंताओं पर गौर करें, तो हाल ही में इस समुद्री रास्ते में कुछ संदिग्ध घटनाएं हुई हैं। कुछ जहाजों पर अनजान प्रोजेक्टाइल से हमला होने की खबर है, जबकि एक और जहाज़ में आग लग गई और उसे खाली कराना पड़ा। इन घटनाओं ने इंटरनेशनल समुद्री व्यापार और एनर्जी मार्केट में चिंताएं बढ़ा दी हैं। स मिलिट्री सोर्स ने दावा किया है कि उन्होंने इस रास्ते में ईरान से जुड़े 16 माइन बिछाने वाले जहाजों को नष्ट कर दिया है। हालांकि इन दावों की अलग से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे यह साफ़ हो जाता है कि यह इलाका अब एक संभावित मिलिट्री लड़ाई का सेंटर बन गया है। समुद्री रास्ते पर ऐसी अस्थिरता दुनिया के व्यापार के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि तेल टैंकरों और मालवाहक जहाजों की सुरक्षा सीधे तौर पर इंटरनेशनल मार्केट की स्थिरता से जुड़ी हुई है।

आज तक आमने सामने
RNI NO -PUNHINO/2013/54688
Printed by Mandeep Kaur, Published by Mandeep Kaur, Owned by Mandeep Kaur & Printed at Dashmash Printers 178-179 Ranjit Nagar, Jalnadhar City, Published 87 Ranjit Nagar Near Bus Stand, Jalandhar, Punjab
Editor Surinder Kumar (SK Saxena)
Responsible for selection of News under the PRB ACT.
All Rights Reserved Reproduction in whole or in Part without Permission in Prohibited, All disputes shall be settled at Jalandhar Jurisdiction only
Faxt No. : 0181-5024001, Conact No : 0181-5077100

आवश्यक सूचना

आज तक आमने-सामने का इस समाचार पत्र में मुद्रित वज्ञिापनों (डिस्पले/क्लासीफाईड) के तथ्यों सबंधी कोई दायित्व नहीं है। महारा समाचार पत्र इनको सत्यापित नहीं करता। पाठकों से अनुरोध है कि वे इन विज्ञापनों पर कार्यवाही करने से पूर्व सभी तथ्यों की स्वयं पुष्टि कर लें। -प्रधान संपादक

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ

राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र

आज तक आमने-सामने

हरियाणा समाचार

Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com

1-15 March 2026

मनदीप कौर, डायरेक्टर

एस. के. सक्सैना, मुख्य संपादक

साल 2026 / संपादक एसके सक्सैना / www aajtakaamnesaamne.com / Help Line 9878552070

चरित्र और निर्णय तय करते हैं जीवन की दिशा–सीजेआई सूर्य कांत

मुख्य न्यायाधीश ने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा, शिक्षा का सही उपयोग ही है सच्ची सफलता

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेवि), महेंद्रगढ़ के प्रांगण में शनिवार को भव्य 12वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वहीं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू व आईआईटी रोपड़ के निदेशक डॉ. राजीव आहूजा समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इनके साथ साथ न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ, न्यायमूर्ति एन. एस. शेखावत, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल चंद्र शेखर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नारनौल नरेंद्र सूरा, उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार व पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ सहित जिला प्रशासन व विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि डिग्री केवल उस ज्ञान की पुष्टि करती है जो वर्षों की मेहनत से अर्जित किया गया है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन की असली दिशा और दशा उसके चरित्र और निर्णय लेने की क्षमता तय करती है। उन्होंने कहा कि जब औपचारिक शिक्षा का ढांचा व्यक्ति के आसपास नहीं रहता, तब वही चरित्र और विवेक उसके मार्गदर्शक बनते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को अपने ज्ञान के साथ–साथ नैतिक मूल्यों और सही निर्णय लेने की क्षमता को भी विकसित करना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने कहा कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए नए अवसरों के द्वार खोलती है। इससे उसकी क्षमताओं का विस्तार होता है, उसकी कमाई की संभावनाएँ बढ़ती हैं और जीवन में आगे बढ़ने के कई रास्ते उपलब्ध होते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि उच्च शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता का साधन नहीं है, बल्कि इसके साथ समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की इमारतों का निर्माण, प्रयोगशालाओं का संचालन और शिक्षकों का वेतन उन संसाधनों से संभव होता है जो जनता के कर से जुटाए जाते हैं। देश के लाखों ऐसे नागरिक हैं जो स्वयं विश्वविद्यालय तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन उनके द्वारा दिए गए कर से ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था

संचालित होती है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षित युवा समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को समझें और सार्वजनिक संस्थाओं जैसे न्यायपालिका, सिविल सेवाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएँ। यही लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने हरियाणा के लोकप्रिय खेल कबड्डी का उदाहरण देते हुए विद्यार्थियों को जीवन का महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कबड्डी में एक रेडर एक ही साँस में विरोधी पाले में प्रवेश करता है और लगातार 卐कबड्डी–कबड्डी卐 का उच्चारण करता रहता है। यह केवल खेल का नियम नहीं, बल्कि अनुशासन और आत्मनियंत्रण का प्रतीक भी है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसे हमेशा यह समझ बनाए रखनी चाहिए कि उसकी सीमाएँ क्या हैं और कब उसे वापस लौटना है उन्होंने कहा कि महान रेडर वही होते हैं जो बिना अति महत्वाकांक्षा के सही समय पर निर्णय लेते हैं और सुरक्षित लौट आते हैं। वहीं डिफेंडर भी तभी सफल होते हैं जब वे एकजुट होकर टीम के रूप में काम करते हैं। इसी प्रकार जीवन में भी व्यक्ति को बड़े सपने देखने चाहिए, लेकिन साथ ही विनम्रता, अनुशासन और सामूहिकता की भावना को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी सफलता के साथ–साथ समाज और संस्थाओं को मजबूत बनाने का संकल्प भी लें, क्योंकि यही किसी भी शिक्षा की वास्तविक कसौटी है। इस अवसर पर आईआईटी रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जिसे विद्यार्थी जीवन भर याद रखते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी हमेशा अपने संस्थान को याद रखें और एक जिम्मेदार पूर्व छात्र (एलुमनाई) के रूप में संस्थान से जुड़े रहें। उन्होंने बताया कि आईआईटी जैसे संस्थानों की सफलता में उनके एलुमनाई का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रो. आहूजा ने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे अपनी शिक्षा और ज्ञान का उपयोग सही दिशा में करें, शॉर्टकट से बचें और ईमानदारी को हमेशा बनाए रखें। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के जीवन को मेहनत और ईमानदारी का प्रेरक उदाहरण बताया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी नई तकनीकों को अपनाकर कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार करें और देश के विकास में योगदान दें। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि स्टार्ट–अप शुरू करके रोजगार देने वाले बनना चाहिए। उन्होंने शोध और नवाचार को देश के विकास की कुंजी बताते हुए कहा कि भारत को एक शोध–प्रधान राष्ट्र बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से अपने गुरु–शिष्य परंपरा, माता–पिता और संस्थान के प्रति सम्मान बनाए रखने का आह्वान किया। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय की रिपोर्ट एवं विद्यार्थियों को अपना आशीर्वाद देते हुए कुलपति प्रोफेसर टंकेशवर कुमार ने कहा कि कुलपति ने कहा कि आज हम सभी के लिए यह गौरव की बात है कि देश के करोड़ों युवाओं की प्रेरणा एवं मार्गदर्शक, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत जी हमारे बीच में हैं वे देश के उस मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने कड़े संघर्ष व मेहनत से जीवन में एक बड़ा मुकाम व कीर्तिमान हासिल किया है। वे देश की युवा शक्ति के लिए एक प्रेरणा हैं। कुलपति ने कहा कि 21वीं सदी में हम विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विकसित देशों की श्रेणी में जाने का रास्ता हमारे महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों से होकर ही जाता है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की और से निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। कुलपति ने कहा कि राष्ट्रीय एवं अतंरराष्ट्रीय मंचो पर हमारी रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है। हमें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में राष्ट्रीय स्तर पर 44 वां स्थान हासिल हुआ है व हरियाणा प्रदेश के विश्वविद्यालयों में हमारी रैंकिंग प्रथम स्थान पर रही है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैकिंग में फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस व इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में हमारी रैकिंग अच्छी रही है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों के 3000 से अधिक शोध पत्र स्कोपस एवं वेब ऑफ साइंस डेटा बेस पर प्रकाशित किए हैं व हमारा एच इंडेक्स 82 है। वर्ष 2025 में ही अकेले हमारे शिक्षकों ने 622 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं जो एक रिकार्ड है। विश्वविद्यालय सभी विभागों, पाठ्यक्रमों व संकायों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में सफल रहा है। वर्तमान में हमारे सभी पाठ्यक्रम एनईपी आधारित हैं। हमने अपने पाठ्यक्रमों में अंतरविषयक पाठ्यक्रमए एसडीजी मेपिंग, वेल्यू एडिड, भारतीय ज्ञान परंपरा, स्किल व वोकेशनल एजुकेशन , मल्टीपल एंट्री एवं एक्जिट की शुरूआत की है। एनईपी के तहत नेशनल क्रेडिट फेमवक मूक कोर्सिज को लागू किया है। आज हमारे सभी पाठ्यक्रम वैश्विक मानको के अनुरूप हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप टीचिंग की गुणवता को सुधारने के लिए ही विभिन्न विभागों में प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के 8 संकाय, 35 विभागों में 90 से अधिक पाठ्यक्रमों में 5000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमने विश्वविद्यालय में अगले अकादमिक सत्र से कुछ नए विभाग व पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। मुझे आशा है कि अगले पांच वर्ष में 10 हजार से अधिक विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे। उन्होंने से विद्यार्थियों से अपने जीवन में विकसित भारत का संकल्प लेने का आहवान किया। कुलपति ने विद्यार्थियों से आहवान किया कि सभी हर समय कुछ नया सीखते रहें। बदलती दुनिया के साथ हम कदमताल तभी कर पाएंगे जब हमेशा विद्यार्थी बन कर कर लाइफ लांग लर्नर बनें रहेंगे। इस मौके पर मैडल व डिग्री प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ सुनील कुमार ने सभी का धन्यवाद करते हुए दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए आभार जताया। कार्यक्रम का सफल संचालन विश्वविद्यालय की छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. रेनु यादव व उप छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉ. नीरज कर्ण सिंह ने किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के सम कुलपति प्रोफेसर पवन शर्मा, एडीसी तरुण पावरिया सहित सभी डीन, डायरेक्टर, विभागाध्यक्ष, शिक्षक एवं जिला प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष की माताजी के निधन पर जताया शोक

कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा

चंडीगढ़, 14 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण की माताजी, श्रीमती प्रेम कौर कल्याण के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती प्रेम कौर कल्याण के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करें। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने दिवंगत माताजी की पुण्य स्मृति को सादर नमन करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

फरीदाबाद को बनाएंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर का आधुनिक शहर : विपुल गोयल

रमन कुमार

चंडीगढ़, हरियाणा के राजस्व एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने शनिवार को फरीदाबाद में फ्लावर फेस्टिवल 2026 का बतौर मुख्यातिथि शुभारंभ किया। उन्होंने नगर निगम फरीदाबाद के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कई वर्षों पहले टाउन पार्क में आयोजित होने वाला फ्लावर शो पुनः शुरू करना एक सराहनीय पहल है। इस कार्यक्रम को साकार करने में नगर निगम की टीम, जनप्रतिनिधियों तथा समाज के विभिन्न वर्गों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद के लोग केवल विकास ही नहीं बल्कि शहर की सुंदरता और हरियाली को लेकर भी सजग हैं। उन्होंने पूर्व में किए गए वृक्षारोपण अभियानों, टाउन पार्क के विकास, इको–वन, नमो–वन, और पार्कों के सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि आने वाले समय में टाउन पार्क के लिए स्वीकृत विकास कार्यों से और बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए वाटर कैनाल और बोटिंग जैसी सुविधाएं शुरू करने की भी योजना है। उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था में सुधार का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि कूड़ा संग्रहण, डोर–टू–डोर कलेक्शन, मैकेनाइज्ड और मैनुअल सफाई, तथा नाइट स्वीपिंग जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है और अगले कुछ महीनों में शहर में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि आगामी 4 अप्रैल को सेक्टर–12 में सुबह 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट में फरीदाबाद को अनेक महत्वपूर्ण सौगातें दी गई हैं और आगे की योजनाओं के लिए उनसे आशीर्वाद लिया जाएगा, साथ ही पहले से करवाये गए विकास कार्यों के लिए उनका धन्यवाद भी किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आग्रह किया, ताकि शहर के विकास से जुड़े मुद्दे मजबूती से रखे जा सकें।

फरीदाबाद आएंगे मुख्यमंत्री, 4 अप्रैल को सेक्टर–12 में होगा बड़ा कार्यक्रम

नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्तमंत्री सदन में पेश किया 2026-27 का बजट

2 लाख 23 हजार 658 करोड़ रुपये का बजट पेश, डबल इंजन सरकार ने विकास को दी नई गति, 2025–26 की तुलना में 10 .3त्न अधिक बजट, हर वर्ग के संतुलित और समावेशी विकास पर जोर, प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप हरियाणा को अग्रणी राज्य बनाने का स्पष्ट रोडमैप –मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, (एजंसी)–हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज बतौर वित्तमंत्री विधानसभा में वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य के समग्र, संतुलित एवं तीव्र विकास की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल वार्षिक आय–व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत–2047' विज़न को साकार करने की दिशा में हरियाणा के उज्ज्वल भविष्य का मजबूत खाका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से वर्ष 2047 तक हरियाणा को आर्थिक, सामाजिक तथा आधारभूत संरचना के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने के लिए निरंतर और योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य का कुल व्यय 2025–26 (संशोधित अनुमान) में 2,02,816.66 करोड़ रुपये था, जिसे 2026–27 में बढ़ाकर 2,23,658.17 करोड़ रुपये किया गया है। यह लगभग 10.3 प्रतिशत की वृद्धि है, जो यह दर्शाती है कि सरकार विकास और वित्तीय अनुशासन–दोनों के बीच संतुलन बनाए हुए है।

उन्होंने कहा कि इस बार कृषि एवं संबद्ध सेवाओं का बजट 7,651.13 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8,319.77 करोड़ रुपये किया गया है, जिसमें 8.74 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, ताकि किसानों की आय बढ़े और खेती को लाभकारी बनाया जा सके। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का बजट 562.19 करोड़ से बढ़ाकर 741.55 करोड़ रुपये किया गया है, जो लगभग 32 प्रतिशत अधिक है। सहकारिता विभाग में 1,156.37 करोड़ से बढ़ाकर 1,970 करोड़ रुपये का प्रावधान कर 70 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा एवं खेल के लिए बजट 21,368.10 करोड़ से बढ़ाकर 23,603.69 करोड़ रुपये किया गया है, जो 10.46 प्रतिशत की वृद्धि है। युवा सशक्तिकरण, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का बजट 1,101.44 करोड़ से बढ़ाकर 1,512.21 करोड़ रुपये किया गया है, जिसमें 37.29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा एवं परिवार कल्याण के बजट को 11,507.11 करोड़ से बढ़ाकर 14,007.28 करोड़ रुपये किया गया है, जो 21.73 प्रतिशत अधिक है।

गृह, नागरिक सुरक्षा एवं कारागार विभाग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इनका बजट 7,904.99 करोड़ से बढ़ाकर 8,475.01 करोड़ रुपये किया गया है, जिसमें 7.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऊर्जा विभाग के बजट को 8,671.37 करोड़ से समायोजित कर 6,868 करोड़ रुपये किया गया है। सामाजिक न्याय,

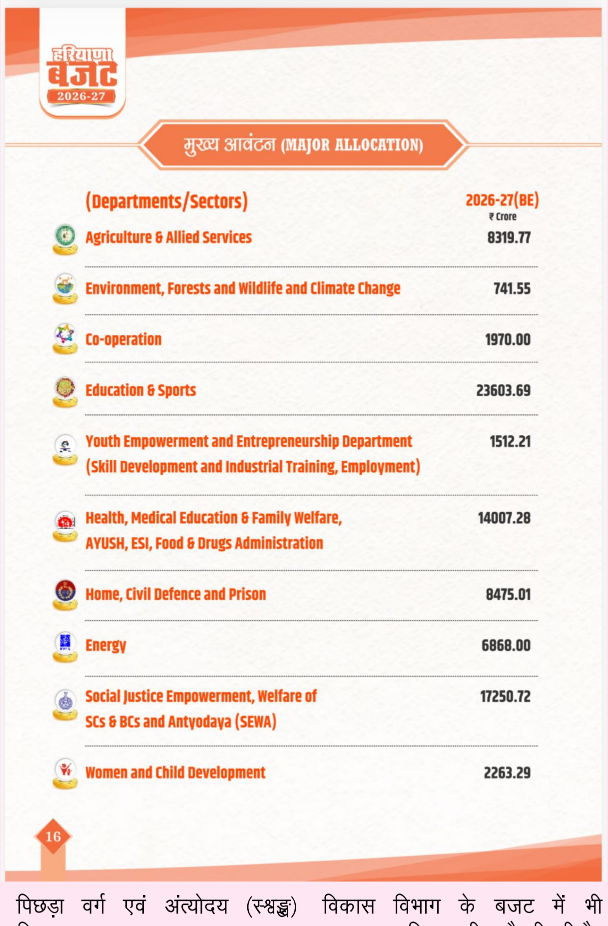

हरियाणा बजट 2026-27

मुख्य आवंटन (MAJOR ALLOCATION)

(Departments/Sectors)	2026-27(BE) ₹ Crore
Agriculture & Allied Services	8319.77
Environment, Forests and Wildlife and Climate Change	741.55
Co-operation	1970.00
Education & Sports	23603.69
Youth Empowerment and Entrepreneurship Department (Skill Development and Industrial Training, Employment)	1512.21
Health, Medical Education & Family Welfare, AYUSH, ESI, Food & Drugs Administration	14007.28
Home, Civil Defence and Prison	8475.01
Energy	6868.00
Social Justice Empowerment, Welfare of SCs & BCs and Antyodaya (SEWA)	17250.72
Women and Child Development	2263.29

16

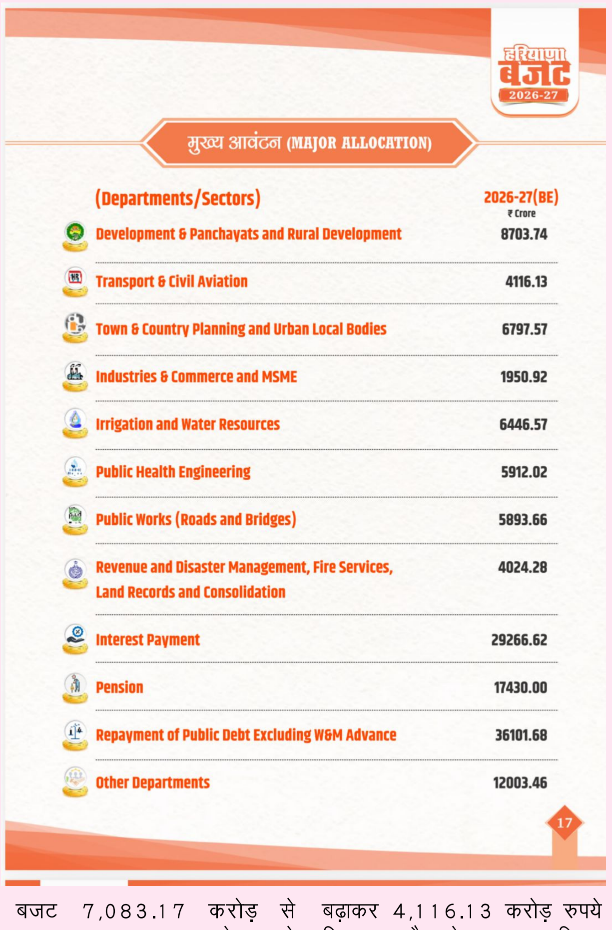

हरियाणा बजट 2026-27

मुख्य आवंटन (MAJOR ALLOCATION)

(Departments/Sectors)	2026-27(BE) ₹ Crore
Development & Panchayats and Rural Development	8703.74
Transport & Civil Aviation	4116.13
Town & Country Planning and Urban Local Bodies	6797.57
Industries & Commerce and MSME	1950.92
Irrigation and Water Resources	6446.57
Public Health Engineering	5912.02
Public Works (Roads and Bridges)	5893.66
Revenue and Disaster Management, Fire Services, Land Records and Consolidation	4024.28
Interest Payment	29266.62
Pension	17430.00
Repayment of Public Debt Excluding W&M Advance	36101.68
Other Departments	12003.46

17

पिछड़ा वर्ग एवं अंत्योदय (स्श्वङ्ग) विभाग का बजट 14,905.24 करोड़ से बढ़ाकर 17,250.72 करोड़ रुपये किया गया है, जिसमें 15.74 प्रतिशत की वृद्धि है।

मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में भी 14.91 प्रतिशत की बढ़ौतरी की है। इस बार का बजट 1,969.65 करोड़ से बढ़ाकर 2,263.29 करोड़ रुपये किया गया है। इसी तरह से ग्रामीण विकास एवं पंचायतों का बजट 7,083.17 करोड़ से बढ़ाकर 8,703.74 करोड़ रुपये किया गया है, जिसमें 22.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के लिए बजट 3,654.54 करोड़ से बढ़ाकर 4,116.13 करोड़ रुपये किया गया है, जो 12.63 प्रतिशत अधिक है।

बजट में शहरों के समुचित विकास पर भी विशेष फोक्स किया गया है, इसके तहत नगर एवं ग्राम नियोजन तथा शहरी निकायों के बजट में 5,444.31 करोड़ से बढ़ाकर 6,797.57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें 24.86 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए भी खास ध्यान रखा गया है। इस बार बजट में उद्योग, वाणिज्य एवं रूस्रूश्व क्षेत्र का बजट 1,327.76 करोड़ से बढ़ाकर 1,950.92 करोड़ रुपये किया गया है। जो लगभग 47 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में ज्यादा ज्यादा उद्योग लगे, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और प्रदेश आर्थिक रूप से और अधिक समृद्ध बने।

किसानों के लिए भी बजट में खासा फोक्स किया गया है। मुख्यमंत्री ने विशेषतौर पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का बजट 5,614.06 करोड़ से बढ़ाकर 6,446.57 करोड़ रुपये किया गया है, यानी 14.83 प्रतिशत अधिक है।

आमजन को पेयजल और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए भी इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का बजट 5,469.22 करोड़ से बढ़ाकर 5,912.02 करोड़ रुपये किया गया है। यह 8.10 प्रतिशत की वृद्धि है। वहीं, लोक निर्माण (सड़कें एवं पुल) विभाग के बजट में 6,096.35 करोड़ से 5,893.66 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजस्व, आपदा प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं एवं भूमि अभिलेख विभाग का बजट 2,180.87 करोड़ से बढ़ाकर 4,024.28 करोड़ रुपये किया गया है, जो 84.53 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि दर्शाता है।

ब्याज भुगतान के लिए बजट 26,497.25 करोड़ से बढ़ाकर 29,266.62 करोड़ रुपये किया गया है, जबकि पेंशन मद में 16,495 करोड़ से बढ़ाकर 17,430 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक ऋण की वापसी के लिए बजट 35,893.33 करोड़ से बढ़ाकर 36,101.68 करोड़ रुपये किया गया है। अन्य विभागों के बजट में 10,263.21 करोड़ से बढ़ाकर 12,003.46 करोड़ रुपये का प्रावधान कर लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। हरियाणा सरकार उसी विज़न के साथ काम कर रही है। 2026–27 का बजट किसान, युवा, महिला, गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग सभी के सशक्त भविष्य की नींव है। हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा 2047 तक विकसित भारत का अग्रणी राज्य बने।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह बजट हरियाणा की तरक्की को तेज़ रफ्तार देगा, रोजगार, निवेश और सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में हरियाणा की भूमिका को निर्णायक बनाएगा।

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ
आज तक आमने-सामने
पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली एवं हरियाणा
Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com
RNI No-Punhin2013/54688

जीसीसी लीडर्स के साथ रणनीतिक परामर्श किया गया-संजीव अरोड़ा

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, मोहाली को एक प्राथमिकता वाले जीसीसी स्थान के रूप में स्थापित करने के लिए पंजाब के दृष्टिकोण, नीतिगत ढांचे और अनुकूल वातावरण को विकसित करने के उद्देश्य से जीसीसी लीडर्स के साथ रणनीतिक परामर्श किया गया। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने जीसीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र विश्व भर में आर्थिक विकास, नवाचार और ज्ञान–आधारित प्रगति के लिए एक शक्तिशाली साधन बन चुका है। तकनीक आधारित निवेशों के लिए मोहाली तेजी से एक पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है, जहां डिजिटल नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए मजबूत प्रतिभा पूल, आधुनिक बुनियादी ढांचा और प्रगतिशील नीति उपलब्ध है। आईटी क्षेत्र की अपार संभावनाओं को स्वीकार करते हुए पंजाब सरकार एक जीवंत वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो सॉफ्टवेयर विकास, डिजिटल सेवाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा विश्लेषण, फिनटेक, साइबर सुरक्षा और उभरते तकनीकी समाधानों के लिए अनुकूल हो। राज्य वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी), प्रौद्योगिकी विकास हब और नवाचार–आधारित स्टार्टअप्स की स्थापना को भी प्रोत्साहित कर रहा है, जो पंजाब को वैश्विक बाजारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मोहाली–चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी कॉरिडोर पहले ही आईटी और आईटी–सक्षम सेवाओं के लिए एक प्रमुख हब के रूप में विकसित हो चुका है, जो प्रमुख कंपनियों को आकर्षित करने के साथ–साथ स्टार्टअप्स, शोध संस्थानों और पेशेवर तकनीकी विशेषज्ञों के साथ एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान हर वर्ष प्रतिभाशाली युवाओं को तैयार कर रहे हैं, जिससे पंजाब तकनीक–आधारित उद्योगों के लिए कुशल मानव संसाधन का मजबूत आधार प्रदान करता है। पंजाब विकास आयोग की वाइस चेयरपर्सन सीमा बंसल ने बताया कि हाल ही में शुरू की गई औद्योगिक नीति प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन ढांचा प्रदान करते हुए आईटी पार्कों, प्रौद्योगिकी कैंपसों, अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं और नवाचार केंद्रों में निवेश को समर्थन देती है। इसके तहत दिए जाने वाले प्रमुख प्रोत्साहनों में पूंजी सब्सिडी, रोजगार सृजन प्रोत्साहन, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति और बुनियादी ढांचा सहायता शामिल हैं, जो कंपनियों को अपना कार्य कुशलता से संचालित करने में सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पंजाब की रणनीतिक स्थिति, मजबूत संपर्क व्यवस्था और उच्च गुणवत्ता वाली जीवन शैली इसे तकनीकी पेशेवरों और वैश्विक कंपनियों के लिए एक आकर्षक स्थान बनाती है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने निवेश को सुगम बनाने के लिए लचीला प्रोत्साहन ढांचा अपनाया है। अब निवेशक 10 से 15 वर्षों के लिए प्रोत्साहन अवधि चुन सकते हैं। आईटी/आईटीईएस इकाइयों और जीसीसी के लिए एफसीआई का कुल 125 प्रतिशत तक प्रोत्साहन तथा डेटा सेंटरों के लिए एफसीआई का 80 प्रतिशत प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रोत्साहन वार्षिक समान किश्तों में वितरित किए जाएंगे। इस गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती श्रेशा जॉर्ज, मैनेजिंग डायरेक्टर और पार्टनर, बीसीजी; श्रीमती शालिनी पिल्ले, इंडिया लीडर – जीसीसी, केपीएमजी इंडिया; श्री शिवराज पलटा, चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर, एवराइज; श्री गौतम झा, लीड एआई/एमएल पार्टनर स्पेशलिस्ट, एडब्ल्यूएस; श्री अचुत्य घोष, एग्जीक्यूटिव रिसर्च लीडर, एचएफएस रिसर्च; डॉ. बिमल दीप सिंह, इंफोसिस; श्री दुश्यंत ठाकोर, डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डब्ल्यूएआईपीए; कार्तिकेयन कुलथुमानी, वाइस प्रेसिडेंट, इन्वेस्ट इंडिया तथा श्री संजीव पाहवा, कोटिविटी जीसीसी उपस्थित थे।

मोहाली को पसंदीदा जीसीसी स्थान के रूप में स्थापित किया जा रहा है–सीमा बंसल

पंजाब डेयरी और पशु पोषण के लिए ग्लोबल हब बनने की राह पर गुरमीत खुड्डियां ने पी. पी. आई. एस-2026 में निवेशकों को किया प्रभावित

पंजाब की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से 3 गुना अधिक, 14.5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन : खुड्डियां

मनदीप कौर

चंडीगढ़, मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की कृषि सहायक क्षेत्रों में नवाचार और किसानों की आर्थिक खुशहाली के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री स.गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन–2026 में वैश्विक निवेशकों के लिए रेड कार्पेट बिछाया। 卐पशु चारा और डेयरी पंजाब- भारत का पशु चारा, पशु पोषण और डेयरी प्रोसेसिंग पावरहाउस卐 में उद्योग के नेताओं और उद्यमियों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने पंजाब को पशु चारा, पशु पोषण और डेयरी क्षेत्र में निवेश के लिए सबसे आकर्षक स्थान बनाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की रूपरेखा दी। स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा, पंजाब आर्थिक खुशहाली और नवाचार की ओर अपनी यात्रा में आपका स्वागत करता है। हमारा विज़न पंजाब को पशुओं के चारे, पशु पोषण और डेयरी सेक्टर में निवेश के लिए सबसे आकर्षक स्थान बनाना है। पशुपालन और डेयरी उत्पादन हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और हम वैश्विक स्तर पर भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं। राज्य की आंतरिक क्षमताओं को उजागर करते हुए, कैबिनेट मंत्री ने पंजाब के शानदार डेयरी उत्पादन का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता लगभग 1,318 ग्राम प्रतिदिन है—जो राष्ट्रीय औसत से लगभग तीन गुना है—सालाना उत्पादन 14.5 मैट्रिक टन से अधिक है। मंत्री ने इस मजबूत प्रदर्शन का श्रेय प्रगतिशील किसानों, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और सहायक सरकारी तंत्र के मेल को दिया। उन्होंने फतेहगढ़ साहिब और राजपुरा में कारगिल एनिमल न्यूट्रीशन एंड हेल्थ और डी ह्यूज़ एनिमल न्यूट्रीशन जैसे वैश्विक दिग्गजों द्वारा स्थापित आधुनिक फीड प्लांट्स की ओर इशारा किया, जो पंजाब के निवेशक–अनुकूल वातावरण के प्रमाण हैं। उत्पादकता और स्थिरता को और बढ़ाने के लिए, कैबिनेट मंत्री ने कई सरकारी पहलों का विवरण दिया, जिसमें सब्सिडी के माध्यम से वाणिज्यिक साइलज उत्पादन को प्रोत्साहित करना और हाइड्रोपोनिक चारा प्रणालियों को बढ़ावा देना शामिल है। कैबिनेट मंत्री ने उच्च–गुणवत्ता वाले उत्पादन को बनाए रखने में शोध और पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, गुरु अंगद देव वैटर्नरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना, बेमिसाल वैज्ञानिक ज्ञान और क्षेत्र–विशेष खनिज मिश्रण प्रदान करती है, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार होता है। एक प्रमुख बाजार अवसर की पहचान करते हुए, स.खुड्डियां ने नोट किया कि राज्य के दूध उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस समय बिना प्रोसेसिंग के खपत किया जाता है। उन्होंने कहा, 卐यह डेयरी प्रोसेसिंग और मूल्य–वर्धित उत्पादों जैसे पनीर, घी, आइसक्रीम और स्वादिष्ट दूध में निवेश के लिए अथाह संभावनाएँ प्रस्तुत करता है। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा, पंजाब सरकार मजबूत बुनियादी ढांचा, मजबूत वैज्ञानिक संस्थान, कुशल सप्लाई चेन और हमारे मेहनती मानव संसाधनों के साथ निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पंजाब के पशुधन क्षेत्र में विशाल अवसरों की पड़ताल करने के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करते हुए स. खुड्डियां ने कहा, मैं यहाँ मौजूद सभी निवेशकों और उद्यमियों को पशु पोषण, डेयरी प्रोसेसिंग और पशुधन विकास में अवसरों की खोज के लिए सीधे आमंत्रित करता हूँ। आइए हम मिलकर पंजाब को कृषि और डेयरी–आधारित उद्योगों के लिए एक ग्लोबल हब बनाएं।卐 पंजाब के विशाल पशु चिकित्सा नेटवर्क का विवरण देते हुए, प्रमुख सचिव पशुपालन श्री राहुल भंडारी ने बताया कि राज्य में 1,367 पशु चिकित्सा अस्पताल, 1,489 डिस्पेंसरी और 22 जिला स्तरीय पॉलीक्लिनिक हैं। इसके अलावा, उच्च स्तरीय मादा डेयरी जानवरों की आबादी बढ़ाने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और लिंग–क्रमबद्ध वीर्य जैसी उन्नत प्रजनन तकनीकों को अपनाया जा रहा है, जिससे भविष्य में और भी उच्च उत्पादकता सुनिश्चित की जा सके। इस अवसर पर डी ह्यूज़ एनिमल न्यूट्रीशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री रटगर ओडेजांस, कारगिल के वाणिज्यिक निदेशक (डेयरी फीड और न्यूट्रीशन) श्री प्रशांत शिंदे और द वैल्यू अल्केमी के संस्थापक श्री संदीप गोयल सहित प्रमुख उद्योग नेता उपस्थित थे।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पंजाब में अपार संभावनाएँ

देश की 20 प्रतिशत ऊर्जा मांग को पूरा करने में पंजाब निभा सकता है अहम भूमिका

कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा

चंडीगढ़, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पंजाब में अपार संभावनाएँ हैं और यह देश की लगभग 20 प्रतिशत ऊर्जा मांग को पूरा करने की क्षमता रखता है। यह विचार पंजाब सरकार द्वारा राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किए जा रहे निवेश सम्मेलन के दौरान नई और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित सत्र में हुई चर्चा के दौरान सामने आए। नई और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित सत्र को संबोधित करते हुए ऊर्जा सचिव बसंत गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार निवेशकों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा पंजाब राज्य को सम्मानित भी किया गया है। श्री गर्ग ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में 1000 मेगावाट क्षमता वाले नई और नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट की स्थापना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि पीएसपीसीएल किसानों और निवेशकों के बीच एक सेतु का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि निवेशकों को भूमि और ग्रिड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जा रही है। श्री गर्ग ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार द्वारा बैटरी पावर स्टोरेज के क्षेत्र में भी कार्य शुरू किया गया है। इस सत्र को संबोधित करते हुए वर्बियो के जनरल मैनेजर अशीष कुमार ने कहा कि पंजाब में हर साल लगभग 20 बिलियन टन पराली का उत्पादन होता है, जो देश की लगभग 20 प्रतिशत ऊर्जा मांग को पूरा करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि किसानों को यह समझने की आवश्यकता है कि जब वे पराली को आग लगाते हैं तो वास्तव में वे अपने पैसे को आग लगा रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के कारण एलपीजी गैस की कमी से उत्पन्न स्थिति के चलते सीबीजी गैस की मांग काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हमें बायोगैस ग्रिड कनेक्टिविटी विकसित करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बशीर अहमद शिराज ने कहा कि यदि किसान बायो–एनर्जी की क्षमता को समझ लें तो उनकी जमीनें सोने की खान बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि नई और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित बुनियादी ढांचे के साथ–साथ एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा लागू की गई नई व्यापारिक नीति नई और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए काफी लाभदायक है। उन्होंने यह भी कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पंजाब में नई और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने की इच्छुक है। सत्र के दौरान हार्टेक इंफ्रा के सिमरनजीत सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी सकारात्मक प्रगति हुई है। उन्होंने पंजाब की औद्योगिक नीति की सराहना करते हुए कहा कि आने वाला समय ऊर्जा का है और हमें इस दिशा में गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आम धारणा है कि अगला युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा, जबकि वास्तव में अगला युग ऊर्जा का है, क्योंकि यदि ऊर्जा होगी तभी एआई जैसी तकनीकें प्रभावी रूप से कार्य कर सकेंगी।

प्रत्येक महिला को सशक्त बनाना, प्रत्येक समुदाय का उत्थान करना-अमृत काल में नारी शक्ति का नया दौर

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी

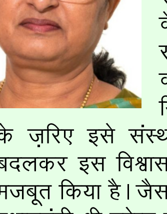

जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो राष्ट्र का उत्थान होता है। समानता और न्याय के मूल्यों पर आधारित समाज में, महिला की गरिमा से कतई समझौता नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमारे समग्र कार्यक्रम–मिशन शक्ति–के ज़रिए इसे संस्थागत ढांचे में बदलकर इस विश्वास को फिर से मजबूत किया है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उचित ही कहा है, 卐हमारी सरकार महिलाओं के लिए 'सम्मान' और 'सुविधा' को सबसे ज़्यादा महत्व देती है।'' ये मार्गदर्शक शब्द केवल भावनाएँ मात्र नहीं, अपितु वह नींव हैं, जिस पर मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति के तहत भारत के कोने–कोने में मज़बूत संस्थागत तंत्र स्थापित किए हैं।

इस प्रयास के केंद्र में मिशन शक्ति की 卐संबल'' उप–योजना के तहत चलने वाले वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) हैं। 2015 में शुरू हुए ये केंद्र हिंसा की शिकार महिलाओं को एकीकृत सहायता तंत्र प्रदान करते हैं, ताकि उन्हें खामोश रहकर पीड़ा न सहनी पड़े और न ही बिखरी हुई सहायता प्रणालियों के बीच भटकना पड़े। आज तक, पूरे भारत में 862 ओएससी चल रहे हैं, जिनसे 12.20 लाख से ज़्यादा महिलाओं को एक ही छत के नीचे कानूनी मदद, चिकित्सा सहायता, पुलिस की मदद, आश्रय और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी एकीकृत मदद मिली है।

डर से आज़ादी तक, खामोशी से सहायता तक – ओएससी ऐसे स्थान हैं जहाँ से घाव भरने की शुरूआत होती है। ये केंद्र प्रतिक्रियात्मक शासन से आगे बढ़कर सक्रिय शासन का रुख करते हैं। चाहे किसी महिला को अपने घर, कार्यस्थल या सार्वजनिक स्थान पर हिंसा का सामना करना पड़े, ओएससी उसके पुनर्वास, गरिमा और न्याय दिलाने में मदद करने के मोदी सरकार के संकल्प का प्रमाण हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केंद्र अस्पतालों के भीतर या उनके पास स्थापित किए गए हैं, ताकि तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके – जो मुश्किल समय में पहला ज़रूरी कदम है। महिला हेल्पलाइन (181) का सार्वभौमीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो संकट से घिरी महिलाओं के लिए 24×7 मदद सुनिश्चित करके ओएससी का पूरक बनता है। 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित यह हेल्पलाइन अब तक 2.56 करोड़ से अधिक कॉल संभाल चुकी है और 93.48 लाख से अधिक महिलाओं की मदद कर चुकी है (30 सितंबर तक)। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस–112) से एकीकृत यह हेल्पलाइन संकट और राहत के बीच की दूरी को पाटती है।

व्यवस्थागत जवाबदेही को मजबूत करने और तेजी से न्याय पहुंचाने के लिए, हमने 745 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं, जिनमें से 404 विशेष पॉक्सो न्यायालय हैं। इन न्यायालयों ने यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय में देरी का मतलब न्याय से इनकार नहीं है, अब तक 3.06 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है। सुनाया गया प्रत्येक फ़ैसला, बहाल किया गया प्रत्येक अधिकार न्यायपूर्ण और लैंगिक समानता वाले भारत की ओर उठाया गया एक कदम है। न्याय मिलना अब प्रक्रियात्मक देरी के कारण बाधित नहीं होता, और प्रत्येक सर्वाइवर समय पर राहत की उम्मीद कर सकता है।

इसके साथ ही, हम पुलिस स्टेशनों पर 14,658 महिला हेल्प डेस्क (डब्ल्यूएचडी) के साथ ज़मीनी स्तर को मज़बूत कर रहे हैं, जिनमें से 13,700 से ज्यादा की कमान महिलाएँ संभाल रही हैं। ये डेस्क सर्वाइवर्स में अपराधों की रिपोर्ट करने का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जिन्हें महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील प्रशिक्षित कार्मिकों की सहायता मिलती है। महिला अधिकारियों की मौजूदगी न केवल आत्मविश्वास बढ़ाती है, बल्कि संस्थागत संवेदनशीलता और जवाबदेही को भी मज़बूत करती है।

हम 807 एंटी–ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (एएचटीयू) के ज़रिए मानव तस्करी से भी निपट रहे हैं और निर्भया कोष के तहत रेलवे और सड़क परिवहन सेवाओं में आपातकालीन निगरानी प्रणालियों की स्थापना के जरिए सुरक्षित गतिशीलता सुनिश्चित कर रहे हैं। ये कदम कि महिलाओं का सुरक्षित रूप से यात्रा करना, निडर होकर काम करना और सार्वजनिक एवं निजी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करना सुनिश्चित करते हैं।

यह एकीकृत दृष्टिकोण सिर्फ़ प्रतिक्रिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रोकथाम, पुनर्वास और सशक्तिकरण तक व्याप्त है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) जैसी पहलों के ज़रिए, हम सोच बदल रहे हैं और सम्मान, बराबरी और अवसर के मूल्य स्थापित कर रहे हैं। पीएमएमवीवाई और सखी निवास के ज़रिए, हम ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, जो महिलाओं को सिर्फ़ सर्वाइवर के तौर पर ही नहीं, बल्कि देश की प्रगति में हितधारकों के तौर पर भी महत्व देती हैं। हमारे सखी निवास हॉस्टल, जिनमें से कई शहरी प्रत्येक और अर्ध–शहरी इलाकों में हैं,– 26,000 से ज्यादा कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती रहने की जगह दे रहे हैं जिससे वे बिना किसी डर के अपने सपने पूरे कर सकती हैं।

मिशन शक्ति के तहत हमारी रणनीति एकीकरण, समन्वय और सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित है। संकल्प- हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ विमेन की शुरुआत के साथ, हमने स्थानीय क्रियान्वयन में एक रणनीतिक परत जोड़ी है, जिससे महिलाएँ एक ही प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कई योजनाओं का लाभ ले सकती हैं। स्थानीय स्तर पर सशक्तिकरण और समन्वय के केंद्र के रूप में कार्य करने वाले इन केंद्रों के ज़रिए 27 लाख से ज़्यादा महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, यह एक राष्ट्रीय सरोकार है। प्रत्येक निर्मित ओएससी, प्रत्येक हेल्पलाइन कॉल जिसका उत्तर दिया गया, और निपटाया गया प्रत्येक मामला, ऐसा भारत बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहाँ प्रत्येक महिला गरिमा, सुरक्षा और गर्व के साथ जीवन जी सके।

जैसे×जैसे हम अमृत काल ×भारत की प्रगति और बदलाव के स्वर्णिम दौर× में कदम रख रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ़ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका है। सशक्त महिलाओं को केंद्र में रखे बगैर 2047 तक विकसित भारत बनाने का विज़न अधूरा है।

नारी शक्ति कोई नारा नहीं है। यह हमारी रणनीति है। यह हमारी ताकत है। यह हमारा भविष्य है। महिलाएं –देखरेखकर्ता, परिवर्तनकर्ता, उद्यमियों और नेतृत्वकर्ताओं के तौर पर – विकसित भारत की रीढ़ हैं। उन्हें सम्मान, सुरक्षा और अवसर देना सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

हमारा सफ़र जारी है, एक समय में एक सशक्त महिला, एक समय में एक सुरक्षित स्थान के साथ। और प्रत्येक कदम के साथ, हम एक मज़बूत, सुरक्षित और अधिक समावेशी भारत का निर्माण कर रहे हैं।

(लेखिका भारत सरकार में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं।)

पंजाब भर में वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई

465 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया

कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा

चंडीगढ़, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री शील नागू की संरक्षण में तथा पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पूरे राज्य में वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के नेतृत्व में आयोजित इस पहल का उद्देश्य विवादों का शीघ्र, कम खर्च में तथा मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटारा करना है, ताकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39–ए के अनुसार न्याय तक पहुंच को बढ़ावा दिया जा सके। लोक अदालत में मुकदमेबाज, न्यायिक अधिकारी, वकील तथा सहयोगी भागीदार शामिल हुए। इस दौरान सिविल, वैवाहिक, संपत्ति, मोटर दुर्घटना दावों, बैंकिंग, बीमा तथा अन्य प्रकार के मामलों सहित कई प्रकार के केसों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। लोक अदालत ने वादकर्ताओं को राहत प्रदान करने के साथ–साथ अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य के सभी जिलों तथा उप–मंडलों में कुल 465 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया था, जिसमें 5,69,425 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से 5,07,372 मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया गया तथा 761 करोड़ रुपये के अवार्ड पास किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से राज्य भर के हजारों मुकदमेबाज थोड़े समय में अपने विवादों का निपटारा करने में सक्षम हुए हैं। इस दौरान एक दशक से अधिक पुराने विवादों सहित लंबित कई मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया, जिससे अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ काफी हद तक कम हो गया। अदालतों को बैंकिंग संस्थाओं, बीमा कंपनियों, सरकारी विभागों तथा आम लोगों से भारी समर्थन मिला, जो लोक अदालतों में लोगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, बरनाला ने एक भूमि विभाजन संबंधी 17 वर्ष पुरानी सिविल अपील का निपटारा करने में सफलता प्राप्त की। यह मुकदमा वर्ष 2009 में शुरू हुआ था, जिसमें 45,000 रुपये की रिकवरी का मामला था। आज सुखदेव सिंह तथा करनैल सिंह के बीच सहमति हो गई। इस मुकदमे को लोक अदालत के पूर्व के निरंतर प्रयासों के माध्यम से आपसी सहमति से हल किया गया। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति जताई, जिससे लंबे समय से चल रहे मुकदमे का अंत हो गया तथा पक्षों के बीच सद्भावना बहाल हुई तथा अंत में इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपील का निपटारा कर दिया गया। श्री मुक्तसर साहिब में राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच के दौरान जसवीर कौर बनाम गुरशरण सिंह नामक लंबे समय से चल रहे गुजारा भत्ते के विवाद का सुलझाव सुलझा लिया गया। लोक अदालत बेंच के हस्तक्षेप से मामला सुलझा लिया गया तथा याचिकाकर्ता को उसके वैवाहिक घर में पुनः बसाया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत, एसएएस नगर के बेंचों ने कई वैवाहिक विवादों में फंसे परिवारों को एक वैवाहिक विवाद में पुनः मिलाया है। मीनू बिष्ट तथा आशीष बिष्ट के बीच छह वर्षों से अधिक समय से चल रहे वैवाहिक विवाद को राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान पारिवारिक अदालत, एसएएस नगर (मोहाली) में सफलतापूर्वक हल कर लिया गया।

यह केस वास्तव में धारा 125 सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता की मांग करते हुए 12.03.2019 को दायर किया गया था। कार्यवाही के दौरान, अदालत द्वारा दोनों पक्षों को अपने विवादों को सुलझाने के लिए मनाया गया। पक्षों ने एक–दूसरे के खिलाफ कई सिविल तथा फौजदारी केस भी दायर किए थे। अंत में, पक्षों ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वैवाहिक संबंधी विवाद का निपटारा कर दिया तथा सभी वैवाहिक संबंधी मुकदमों पर पूर्ण विराम लगा दिया। जिला अदालतों, एसएएस नगर (मोहाली) में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान सौरभ उप्पल तथा स्मृति उप्पल के बीच एक अन्य लंबे समय से लंबित वैवाहिक विवाद का सुलझाव सुलझा लिया गया। यह मामला नाबालिग बच्चे के मिलने के अधिकारों संबंधी संरक्षक तथा वार्ड एक्ट के तहत दायर याचिका से संबंधित था। अदालत के हस्तक्षेप तथा कई काउंसलिंग बैठकों के बाद, दोनों पक्ष एक समझौते के लिए सहमत हो गए तथा शांति से साथ रहने का फैसला किया। इस प्रकार लंबे समय से चल रहा विवाद सुलझ गया तथा जोड़ा अपने बच्चे सहित अदालत के परिसर से बाहर चला गया।

इस अवसर पर पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा ने राज्य भर के न्यायिक अधिकारियों, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरणों तथा स्वयंसेवकों के समर्पित प्रयासों की प्रशंसा की, जिनकी सामूहिक प्रतिबद्धता ने इस मेगा कार्यक्रम को सफल बनाया।

पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, सभी जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरणों, राज्य न्यायपालिका, बार सदस्यों, पुलिस अधिकारियों तथा सिविल प्रशासन का उनके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद किया।

सर्विसेज़ के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन

जालंधर में 72वीं इंटर–सर्विसेज़ हॉकी चैंपियनशिप का समापन

एस. के. सक्सैना

जालंधर, 72वीं इंटर–सर्विसेज़ हॉकी चैंपियनशिप 2025–26 का समापन जालंधर के आर्मी हॉकी नोड (।ढ्ढ) स्थित वज्र एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में एक भव्य समापन समारोह के साथ हुआ। यह आयोजन आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में किया गया था। वज्र कोर द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में सर्विसेज़ के बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी एक साथ आए, जिन्होंने असाधारण कौशल का प्रदर्शन करते हुए खेल भावना, शारीरिक उत्कृष्टता और सर्विसेज़ के बीच आपसी भाईचारे की भावना को और मज़बूत किया। 09 से 13 मार्च 2026 तक आयोजित इस टूर्नामेंट में आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना की टीमों ने %राउंड रॉबिन लीग% फ़ॉर्मेट में एक–दूसरे से मुक़ाबला किया। चैंपियनशिप का समापन आर्मी रेड और भारतीय नौसेना के बीच एक रोमांचक फ़ाइनल मैच के साथ हुआ, जिसमें आर्मी रेड ने पेनल्टी शूटआउट के ज़रिए 6–5 से जीत हासिल की। फ़ाइनल मैच बेहद रोमांचक रहा, जिसमें खेल की तेज़ रफ़्तार, बेहतरीन रणनीतियाँ और खिलाड़ियों के असाधारण %स्टिक वर्क% ने दर्शकों को मैच की आख़िरी सीटी बजने तक अपनी सीटों से बांधे रखा। इस चैंपियनशिप में स्थानीय समुदाय, पूर्व सैनिकों और खेल प्रेमियों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस आयोजन के ज़रिए सर्विसेज़ हॉकी की गौरवशाली विरासत का जश्न मनाया गया और युवाओं को खेल तथा राष्ट्र सेवा के माध्यम से उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया गया। जालंधर स्थित आर्मी हॉकी नोड, सर्विसेज़ के भीतर सुनियोजित प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धी माहौल उपलब्ध कराकर बेहतरीन हॉकी प्रतिभाओं को निखारने में लगातार एक अहम भूमिका निभा रहा है। पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ़, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार (क्क्कस्रू, ड्डस्रू, ङ्कस्रू) ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह की शोभा बढ़ाई। इस समारोह में हॉकी जगत की जानी–मानी हस्तियाँ, पूर्व ओलंपियन, स्नद्ध॥ के अधिकारी, हॉकी इंडिया के चयनकर्ता और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। इन सभी ने खिलाड़ियों से बातचीत की और उभरती हुई प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन किया। इस कार्यक्रम का समापन एक जीवंत सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ हुआ, जिसमें पंजाब के समृद्ध नृत्य और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिली। इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।

राइट टू सर्विस कमीशन ने आवेदकों को मुआवजा देने का दिया आदेश

पंकज

चंडीगढ़, 14 मार्च –– हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने फरीदाबाद की भावना गुप्ता और अमनदीप से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि संबंधित भूमि पर वर्ष 2009 से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत स्थगन (स्टे) लागू है। इसके बावजूद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा 18 जनवरी, 2023 और 22 मार्च, 2023 को उक्त प्लॉट्स की नीलामी कर दी गई। आयोग ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह न्यायालय की अवमानना के साथ–साथ धोखाधड़ी से संबंधित दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत भी आ सकता है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि यदि किसी निजी कॉलोनाइजर द्वारा बिना वैध स्वामित्व के प्लॉट बेचा जाता, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाती। आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि इस मामले के तथ्य संजीव वर्मा और हिमांशु शर्मा से संबंधित पूर्व मामलों के समान हैं, जिनका निपटारा आयोग द्वारा 19 फरवरी, 2026 को किया जा चुका है। इसी आधार पर आयोग ने वर्तमान संशोधन याचिकाओं का निपटारा करते हुए हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट की धारा 17(1)(ह) के तहत दोनों रिवीजनिस्ट्स को 5,000–5,000 रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने एचएसवीपी को आदेश दिया है कि यह राशि 15 दिनों के भीतर अदा की जाए और 30 मार्च, 2026 तक इसकी अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि एचएसवीपी प्रारंभ में यह राशि अपने फंड से दे सकता है, जिसे बाद में जांच के बाद दोषी अधिकारियों से वसूल किया जा सकता है। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आवेदक यदि चाहें तो मानसिक पीड़ा, आर्थिक नुकसान और अन्य परेशानियों के लिए अधिक मुआवजे की मांग हेतु उपभोक्ता फोरम, माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण का रुख कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि चूंकि मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में प्लॉट का कब्जा सुनिश्चित कराना संभव नहीं है। आयोग ने उम्मीद जताई कि एचएसवीपी इस मामले को कानूनी रूप से उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए प्रयास जारी रखेगा।

आईएसआई की सहायता प्राप्त हथियार तस्करी माड्यूल का पर्दाफाश; ए के -47 राइफल समेत चार हथियारों के साथ दो आरोपी अमृतसर से काबू

माड्यूल कट्टरपंथी गतिविधियों और भारत–विरोधी तथा पुलिस–विरोधी बयानों को फैलाने में शामिल था : डीजीपी गौरव यादव

रमन कुमार

चंडीगढ़/अमृतसर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा–निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए जारी अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आईएसआई की सहायता प्राप्त सीमा–पार से हथियारों की तस्करी करने वाले और आतंकवादी माड्यूल का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों के पास से चार अत्याधुनिक हथियार, जिनमें दो मैगज़ीन और 36 जिंदा कारतूस समेत ए के –47 राइफल शामिल है, बरामद किए हैं। यह जानकारी आज यहां निदेशक जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गुरसेवक सिंह उर्फ सूरज निवासी नई आबादी, अटारी, अमृतसर और अमरजीत सिंह उर्फ रोहित निवासी सुभाष रोड छेहरटा, अमृतसर के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने आरोपियों के कब्जे से ए के –47 राइफल बरामद करने के अलावा तीन अत्याधुनिक 9एमएम ग्लोक पिस्टल भी बरामद किए हैं। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार उक्त आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि यह माड्यूल कट्टरपंथी गतिविधियों और भारत–विरोधी तथा पुलिस–विरोधी बयानों को फैलाने जैसी गतिविधियों में भी शामिल था। डीजीपी ने कहा कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए इस मामले में पिछले–पिछले संबंधों की जांच की जा रही है। ऑपरेशन के विवरण साझा करते हुए सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) अमृतसर ग्रामीण सुहेल कासिम मीर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना घरिंडा की टीमों ने गांव मुहावा से दो संदेहियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियारों की खेप, जिसमें ए के –47 समेत गोलियाँ और तीन ग्लोक पिस्टल शामिल हैं, बरामद की। एसएसपी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि हथियारों की यह खेप पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से माड्यूल के विदेशी हैंडलरों द्वारा पाकिस्तान के रास्तों से भेजी गई थी। इस संबंध में थाना घरिंडा में आर्म्स एक्ट की धाराओं 25(1)(ए), 25(6), 25(7), 25(8) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकू) एक्ट (यूएपीए) की धाराओं 13, 16, 18 के तहत एफ.आर.आई.संख्या 80 दिनांक 12.03.2026 दर्ज की गई है।

विदेशी हैंडलरों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के रास्तों से भेजी गई थी हथियारों की खेप: एसएसपी सुहेल कासिम मीर

भारत ने वैश्विक मंच पर रखा कदम

गिरिराज सिंह

भारत ने वैश्विक मंच पर ऐसा कदम रखा है, जिसे दुनिया अनदेखा नहीं कर सकी। 16वें भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) औपचारिक रूप से पूरा हुआ। यह एक ऐतिहासिक पल था, जिस पर दशकों से काम हो रहा था। यह समझौता दूरदृष्टि, दृढ़ संकल्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत आर्थिक नेतृत्व का परिणाम है।

भारत और यूरोपीय संघ मिलकर दुनिया की चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों मिलकर वैश्विक जीडीपी का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं। जब इन दोनों बड़े आर्थिक भागीदारों ने भारत–ईयू मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया, तो यह केवल एक और व्यापार समझौता नहीं रहा, बल्कि अपने आकार और रणनीतिक महत्व के कारण यह एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक समझौता बन गया।

भारत–ईयू एफटीए तक की यह यात्रा शासन के तरीके में साफ अंतर दिखाती है। वर्ष 2014 से पहले भारत को केवल 19 देशों में व्यापार की पहुंच थी, जबकि आज यह संख्या 56 देशों तक पहुंच गई है। केवल भारत–ईयू एफटीए से ही 27 बड़े और महत्वपूर्ण बाजारों तक पहुंच खुली है। यह स्पष्ट, परिणाम आधारित और मजबूत शासन का प्रतीक है।

आज वैश्विक वस्त्र और परिधान बाजार का आकार 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका है। यह दुनिया भर में बढ़ती मांग और तेज़ बदलाव को दिखाता है। दुनिया का कुल आयात वर्ष 2001 में 366.8 अरब डॉलर था, जो बढ़कर 2024 में लगभग 800 अरब डॉलर हो गया है। इससे साफ है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। इसी वैश्विक माहौल में भारत ने भी अपनी स्थिति लगातार मज़बूत की है। भारत का कुल टेक्सटाइल निर्यात लगभग 10 अरब डॉलर से बढ़कर करीब 40 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इससे वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी काफ़ी मजबूत हुई है।

देश के भीतर भी टेक्सटाइल क्षेत्र में तेज़ बढ़त देखी जा रही है। भारत का घरेलू टेक्सटाइल बाजार 138 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में लगभग 190 अरब डॉलर हो गया है। इसका मुख्य कारण उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग और लोगों की बढ़ती खरीद क्षमता है। यह वृद्धि कई नीतिगत सुधारों और सरकारी पहलों से संभव हुई है, जिनसे उत्पादन व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया, सप्लाई और वैल्यू चेन को मज़बूत किया गया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ी।

इसी पृष्ठभूमि में भारत–ईयू मुक्त व्यापार समझौते का महत्व बहुत ऐतिहासिक बन जाता है। यह समझौता यूरोपीय यूनियन के पूरे बाजार तक भारत की पहुंच खोलता है, जहां लगभग 2 अरब उपभोक्ता हैं और कुल बाजार का आकार करीब 24 ट्रिलियन डॉलर है।

इस समझौते के तहत मूल्य के हिसाब से भारत के 99 प्रतिशत से अधिक निर्यात को विशेष (प्राथमिक) व्यापार सुविधा मिलेगी। साथ ही लगभग 33 अरब डॉलर के सामान पर लगने वाले 10 से 12 प्रतिशत तक के शुल्क (टैरिफ) खत्म हो जाएंगे। इससे दुनिया के सबसे प्रीमियम बाजारों में भारत के उत्पाद और अधिक सस्ते व प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

पिछले दो वर्षों में हमने जीडीपी, मांग के रुझान, जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय जैसे आँकड़ों के आधार पर एक नई बाजार विविधीकरण (मार्केट डाइवर्सिफिकेशन) रणनीति तैयार की और उसे आगे बढ़ाया।

अब इस रणनीति के साफ़ नतीजे दिखने लगे हैं। वर्ष 2025 में, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत के टेक्सटाइल निर्यात ने 100 से अधिक देशों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। इससे दुनिया में भारत की मौजूदगी और मजबूत हुई है।

इस लक्षित रणनीति के तहत निर्यात में तेज़ बढ़ोतरी हुई है। अर्जेंटीना में 77 प्रतिशत, पराग्वे में 45 प्रतिशत और इजिप्ट में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से रेडीमेड कपड़ों के कारण हुई है। इसके पीछे पिछले दस वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का लगातार विस्तार रहा है। बीते दस सालों में भारत के उत्पादन तंत्र में 2 करोड़ से अधिक सिलाई मशीनें जोड़ी गई हैं। इससे उत्पादन बढ़ा है, काम की उत्पादकता बेहतर हुई है और रोज़गार के नए अवसर बने हैं। इस विस्तार को मजबूत नीतिगत समर्थन भी मिल रहा है। केंद्रीय बजट 2026–27 में टेक्सटाइल क्षेत्र को भारत की विकास रणनीति के केंद्र में रखा गया है। इसके तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क, एकीकृत वैल्यू चेन, टिकाऊ उत्पादन से जुड़ी पहल और 'समर्थ 2.0' के तहत कौशल विकास पर ज़ोर दिया गया है। इसके साथ ही, प्रमुख टेक्सटाइल क्लस्टरों में टेक्सटाइल निर्यात सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। ये केंद्र एक ही मंच पर निर्यातकों को बाजार से जुड़ी जानकारी, एफटीए से संबंधित मार्गदर्शन, नियमों में सहायता और शुरुआत से अंत तक पूरी सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात के लक्ष्य के साथ, भारत की टेक्सटाइल रणनीति बड़े पैमाने, तेज़ रफ्तार और वैश्विक सोच को दिखाती है।

भारत–ईयू मुक्त व्यापार समझौता इस गति को और मजबूत करता है। यह केवल एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी है, जिसके तहत भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच कुल व्यापार और सहयोग को 2030 तक 179 अरब डॉलर से बढ़ाकर 350 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। आज भारत सिर्फ वैश्विक व्यापार का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसे दिशा देने वाला देश बन रहा है।

(लेखक केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं। यक्त किए गए विचार उनके निजी हैं।)

सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना-किफायती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के लिए जनऔषधि परियोजना का रणनीतिक विकास

श्री जगत प्रकाश नड्डा

जन औषधि सस्ती भी, भरोसेमंद भी, सेहत की बात, बचत के साथ।

किसी राष्ट्र की प्रगति का असली पैमाना अक्सर इस बात से परिलक्षित होता है कि उसके नागरिक स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक कितनी आसानी से पहुँच सकते हैं। दशकों तक, भारत के लाखों लोगों के स्वास्थ्य और

आरोग्य के लिए दवाओं की उच्च लागत एक प्रमुख वित्तीय बाधा रही है। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी), प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं को उनके ब्रांडेड समकक्षों की तुलना में काफी कम कीमत पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल है। यह परियोजना सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में एक महत्वपूर्ण कमी को दूर करके एक व्यापक और व्यवस्थित परिवर्तन लाने में सफल रही है।

वैश्विक स्तर पर, जेनेरिक दवाइयाँ सुलभ स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की मूलभूत आधारशिला हैं। विश्व भर में चिकित्सकों द्वारा दी जाने वाली कुल दवाइयों में इनकी हिस्सेदारी लगभग 80–90ब्र है और इसने आवश्यक दवाओं तक पहुँच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि जेनेरिक दवाइयाँ पैकेज, लेबल और निष्क्रिय अवयव की दृष्टि से भिन्न हो सकती हैं, लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि ये अंतर उनके चिकित्सीय प्रभाव पर असर नहीं डालते हैं। खुराक, सुरक्षा, क्षमता, गुणवत्ता और लक्षित उपयोग के संदर्भ में जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की समकक्ष हैं तथा उत्पादन और गुणवत्ता के कठोर मानकों का समान रूप से पालन करती हैं।

पीएमबीजेपी केवल एक खुदरा–बिक्री कार्यक्रम नहीं है; यह भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के संरचनात्मक सशक्तिकरण को दर्शाता है। यह इस साल के जनऔषधि सप्ताह के थीम में परिलक्षित होता है, ﬓजन औषधि सस्ती भी, भरोसेमंद भी, सेहत की बात, बचत के साथﬓ, यह थीम लाखों लाभार्थियों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है। 18,000 से अधिक जनऔषधि केंद्रों के तेजी से बढ़ते नेटवर्क के माध्यम से, योजना ने सुनिश्चित किया है कि दवाइयाँ बाजार दरों की तुलना में 50ब्र से 80ब्र तक की कम कीमतों पर उपलब्ध हों और सभी सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों को समर्थन प्रदान करती हों। क्षेत्र सर्वेक्षणों से पता चला है कि लाभार्थी लागत बचत और दवाइयों तक बेहतर पहुँच की सराहना करते हैं।

योजना का पैमाना इसके उत्पाद

संग्रह से भी परिलक्षित होता है। जनऔषधि 2,110 दवाओं और 315 सर्जिकल उत्पादों का विस्तृत संग्रह पेश करता है, जो 29 विभिन्न चिकित्सीय क्षेत्रों को शामिल करती है। भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) के प्रत्यक्ष देखरेख में, संग्रह का विस्तार एक गतिशील, डेटा–संचालित प्रक्रिया है, जिसमें बाजार विश्लेषण, हितधारकों की भागीदारी और एक समर्पित विशेषज्ञ समिति की कठोर निगरानी शामिल हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि योजना देश की बदलती स्वास्थ्य आवश्यकताओं और औषधीय मांगों के अनुरूप विकसित होती रहे।

कठोर नियामक निरीक्षण के साथ, भारतीय दवा कंपनियां 200 से अधिक देशों के लिए भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बन गई हैं, जिसमें अमेरिका, यूके और यूरोपीय संघ जैसे अत्यधिक विनियमित बाजार भी शामिल हैं। भारतीय दवा कंपनियां लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप जैसे उभरते बाजारों में भी विस्तार कर रही हैं।

यह उद्योग जैविक दवाओं के समान दवाओं (बायोसिमिलर), जैविक दवाओं के जेनेरिक प्रतिरूपों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, साथ ही जटिल जेनेरिक और विशेष दवाओं का उत्पादन करने के लिए अनुसंधान और विकास में भी अधिक निवेश कर रहा है। ये दूरदर्शी कार्यक्रम भारत को न केवल एक वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में, बल्कि किफायती दवाओं के क्षेत्र में भविष्य के नवाचार अग्रणी देश के रूप में भी स्थापित करते हैं।

गुणवत्ता बनाम मूल्य पर बहस कभी–कभी सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करती है। एक बहु–स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन व्यवस्था के माध्यम से,पीएमबीजेपी ने इस मिथक को प्रभावी ढंग से तोड़ दिया है कि किफायती होना निर्माण मानकों में समझौते का संकेत देता है। दवाइयाँ डब्ल्यूएचओ–जीएमपी प्रमाणित निर्माताओं से खरीदी जाती हैं, जो वैश्विक उत्पादन मानकों का पालन सुनिश्चित करती हैं। नियम निर्धारित करते हैं कि फार्मेसी की शेल्फ तक पहुंचने से पहले दवा के हर बैच का राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा स्वीकृत प्रयोगशालाओं में सख्त सत्यापन होना आवश्यक है। ये दवाइयाँ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के नियमों का पालन करती हैं और ब्रांडेड विकल्पों के सुरक्षा और प्रभावशीलता मानकों के अनुरूप हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खरीद से पहले सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाती है और खरीद के बाद प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी, पीएमबीआई नियमित रूप से दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी और समीक्षा करती है, ताकि स्थापित विनियमों के पालन में कोई कोताही न होना सुनिश्चित किया जा सके। एक आईटी–संचालित वितरण नेटवर्क, जिसे पांच अत्याधुनिक भंडार गृहों और देशभर के में 41 विशेष वितरकों का समर्थन प्राप्त है, ने सुनिश्चित किया है कि आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के खिलाफ सुदृढ़ बनी रहे।

तीन स्तंभों – पहुँच, गुणवत्ता और सस्ती कीमत – पर ध्यान केंद्रित करके, पीएमबीजेपी ने लाखों लोगों के चिकित्सा खर्च को काफी हद तक कम कर दिया है। निरंतर संस्थागत समर्थन, लोगों की बढ़ती जागरूकता और अवसंरचनात्मक सुधारों के साथ, हर जिले में जनऔषधि केंद्र का सपना अब दूर की आकांक्षा नहीं, बल्कि यह ठोस रूप ले चुका है और वास्तविकता के करीब है।

'विकसित भारत श्र2047% दृष्टि के तहत मुख्य ध्यान इस बात पर है कि हर किसी के लिए एक सुदृढ़, न्यायसंगत और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाई जाए। इसमें बेहतर अस्पताल, कम चिकित्सा खर्च, उपचार तक आसान पहुंच और सस्ती दवाओं की उपलब्धता शामिल हैं। बहु–क्षेत्रीय सहयोगों के जरिये, पीएमबीजेपी ने यह साबित किया है कि सही संस्थागत दृष्टि के साथ, स्वास्थ्य सेवा उच्च गुणवत्ता युक्त और सार्वभौमिक रूप से सुलभ दोनों हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यह परियोजना प्रगति करती रहे और किफायती स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मॉडल के रूप में अपनी स्थिति को निरंतर बनाए रखे।

(लेखक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं)

ध्रुवीकृत विश्व में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता

Dr. M Chuba Ao
National Vice President, Bhartiya Janta Party

आज का वैश्विक परिदृश्य तेजी से ध्रुवीकृत होता जा रहा है। एक ओर अमेरिका, चीन और रूस जैसी महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र हो रही है, तो दूसरी ओर यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया तक के संघर्ष दुनिया के देशों पर किसी एक पक्ष

का साथ देने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे दौर में भारत ने जिस नीति को दृढ़ता से अपनाया है, वह है रणनीतिक स्वायत्तता—एक ऐसी नीति जो भारत को अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र और संतुलित निर्णय लेने की शक्ति देती है।

यह केवल शीत युद्ध के समय की पारंपरिक गुटनिरपेक्षता का पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक परिपक्व और सक्रिय दृष्टिकोण है। आज भारत मल्टी–अलाइनमेंट यानी बहु–संतुलन की नीति पर काम कर रहा है—जहाँ वह विभिन्न देशों के साथ उनके गुणों और पारस्परिक हितों के आधार पर सहयोग करता है, पर किसी एक गुट का स्थायी हिस्सा बनने से बचता है। इस नीति का मूल उद्देश्य स्पष्ट है—भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि।

रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ है कि भारत अपने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और संप्रभुता से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले सके। एक ऐसे बहुध्रुवीय विश्व में, जहाँ वैश्विक व्यवस्था लगातार बदल रही है, यह नीति भारत को जोखिमों को संतुलित करने, निर्भरता के स्रोतों को विविध बनाने और अपने प्रभाव को मजबूत करने का अवसर देती है।

इसका उदाहरण स्पष्ट रूप से

भारत की वैश्विक साझेदारियों में देखा जा सकता है। भारत क्वाड जैसे मंचों के माध्यम से अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग को मजबूत कर रहा है। वहीं दूसरी ओर, रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में दीर्घकालिक और विश्वसनीय साझेदारी बनाए हुए है। इसी के साथ, सीमा विवाद के बावजूद भारत चीन के साथ आर्थिक संबंधों को भी पूरी तरह समाप्त नहीं करता। यह संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि कोई भी शक्ति भारत की विदेश नीति को नियंत्रित न कर सके।

पश्चिम एशिया में भारत की नीति इस रणनीतिक संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत ने इज़राइल के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुँचाया है। रक्षा क्षेत्र में संयुक्त रूप से विकसित बराक–8 मिसाइल प्रणाली, कृषि क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई तकनीक पर आधारित 33 से अधिक उत्कृष्टता केंद्र, जल प्रबंधन में डिसेलिनेशन और पुनर्चक्रण तकनीक, तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान—ये सभी इस सहयोग के ठोस परिणाम हैं।

दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार लगभग 3.75 अरब डॉलर (वित्त वर्ष 2024–25) तक पहुँच चुका है और फरवरी 2026 में शुरू हुई मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ताएँ उच्च–प्रौद्योगिकी तथा एमएसएमई क्षेत्रों में नई संभावनाएँ खोल सकती हैं।

हालाँकि, इज़राइल के साथ गहराते संबंधों के बावजूद भारत की क्षेत्रीय नीति संतुलित बनी हुई है। भारत संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे अरब देशों के साथ ऊर्जा, अवसंरचना और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी बनाए हुए है। साथ ही, भारत फिलिस्तीन के लिए दो–राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है और मानवीय सहायता भी प्रदान करता है। ईरान जैसे देशों के साथ भी भारत संवाद और सहयोग का रास्ता खुला रखता है।

हाल के घटनाक्रम—जैसे फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज़राइल यात्रा—भारत की डी–हाइफ़नेशन नीति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इसका अर्थ है कि भारत अपने द्विपक्षीय संबंधों को अलग–अलग आधारों पर आगे बढ़ाता है, बिना किसी अन्य देश को अलग–थलग किए। यह व्यवहारिक कूटनीति भारत को क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के साथ–साथ वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने का अवसर देती है।

आज के ध्रुवीकृत दौर में रणनीतिक स्वायत्तता भारत के लिए एक सुरक्षा कवच भी है और अवसरों का सेतु भी। यह नीति भारत को ऐसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती है जो सीधे नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं—चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा हो, खाद्य और जल सुरक्षा हो, या नवाचार के माध्यम से रोजगार के नए अवसर।

जैसे–जैसे वैश्विक विभाजन गहराता जा रहा है, भारत की यह स्वतंत्र और हित–आधारित कूटनीति एक परिपक्व मार्ग प्रस्तुत करती है। यह न तो किसी से दूरी बनाने की नीति है और न ही अनिश्चितता की। बल्कि यह एक आत्मविश्वासी और संतुलित दृष्टिकोण है, जिसके माध्यम से भारत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को विकास, शांति और समानता के हित में आकार देने का प्रयास कर रहा है।

अपडेटेड जीडीपी- डेटा आधारित युग में निर्णयों को आकार देना

श्री सौरभ गर्ग

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की ओर से नए आधार वर्ष 2022–23 पर आधारित जीडीपी आँकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था ने संशोधित आधार के बावजूद मजबूत वृद्धि बनाए रखी है, जिसमें 2023–24 से 2025–26 के लिए औसत

वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7 प्रतिशत से अधिक और इसी अवधि के लिए औसत नाममात्र जीडीपी वृद्धि 9 प्रतिशत से अधिक रही है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए दूसरे उन्नत अनुमानों के अनुसार, वास्तविक जीडीपी 7.6 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि नाममात्र जीडीपी 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर रहा है।

इन आँकड़ों का महत्व तब और भी ज़्यादा साफ़ हो जाता है, जब इन्हें अनेक तरीकों में बदलाव और आधार वर्ष संशोधन के दौरान अपनाए गए नए डेटा स्रोतों की पृष्?ठभूमि में देखा जाता है। अन्?य के अलावा, अप?स्?फीति या डिफ्लेशन की अधिक परिष्कृत विधियों को अपनाए जाने तथा वार्षिक सर्वेक्षण के निष्कर्षों और व्यापक प्रशासनिक डेटा सेट जैसे समृद्ध डेटा स्रोतों के समावेश– ने अर्थव्यवस्था की बदलती प्रवृत्तियों को और स्पष्ट रूप से समझने में मदद की है। यह बात भारत की जीडीपी पद्धति में बड़े पैमाने पर दिलचस्?पी को देख?ते हुए भी मायने रखती है, जिसने अक्सर अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर चर्चा को बढ़ावा दिया है।

संशोधित जीडीपी आँकड़े केवल सांख्यिकीय संख्याएँ नहीं दर्शाते; बल्कि खामोशी से यह भी दर्शाते हैं कि विभिन्न सरकारी पहलें विकसित भारतश्र2047 के व्यापक विजन को आगे बढ़ाते हुए नीतियों को किस प्रकार ठोस क्षेत्रीय परिणामों में तब?दील कर रही हैं।

विनिर्माण क्षेत्र ने वर्ष 2023–24 से 2025–26 के बीच औसतन 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो इस बात का स्?पष्?ट उदाहरण है कि डबल डिफ्लेशन के उपयोग और नए डेटा स्रोतों को अपनाने जैसी परिष्कृत पद्धतियों ने किस प्रकार इस क्षेत्र की वास्तविक गति को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाया है। यह ऐसी गति है, जिसको सरकार उत्पादन–आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना सहित विभिन्न योजनाओं के जरिए सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

नई श्रृंखला में, मूल्य संवर्धन में कृषि के योगदान में वृद्धि मुख्यतः डीजल के उपयोग में कमी त?था

ज?यादा कीमत वाले फलों एवं सब्जियों के योगदान को शामिल किए जाने के कारण हुई है। ये सकारात्मक संकेत हैं, जो लागत का दबाव कम होने, सरकार के प्रोत?साहन के कारण किसानों द्वारा सौर ऊर्जा को अपनाए जाने और उच्च मूल्य वर्द्धित कृषि की ओर नीति–प्रेरित बदलाव को दर्शाते हैं। इससे खेती की लाभप्रदता मजबूत होती है और किसानों की आय में सुधार होता है।

असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) जैसे नए सर्वेक्षण डेटा के उपयोग ने मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र प्रधान सेवा क्षेत्रों, जैसे व्यापार, परिवहन और अन्य सेवाओं में जीडीपी अनुमान को नया रूप दिया है। पहले इन उद्यमों के लिए गणनाएँ सीधे आँकड़ों के बजाय बेंचमार्क आधारित अनुमानों पर निर्भर करती थीं।

उदाहरण के लिए, व्यापार, होटलों, परिवहन और संचार उप–क्षेत्र ने 2023–24 से 2025–26 के तीन वर्षों में औसतन 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। आंशिक रूप से यह बेहतर डेटा उपयोग का परिणाम है, क्योंकि एएसयूएसई और पीएलएफएस जैसे सर्वेक्षण मौजूदा रुझानों को उजागर करते हुए अब अनौपचारिक क्षेत्र और श्रमिकों की उत्पादकता को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बनाते हैं। इसी तरह, अद्यतन डेटा स्रोतों के उपयोग ने आवासीय संपत्तियों के स्वामित्व में वृद्धि को दर्ज किया है, जो सरकार की किफायती आवास योजनाओं के सकारात्मक परिणामों को दर्शाता है।

जीडीपी अनुमान नए डिजिटल डेटा स्रोतों से लाभान्वित हुआ है, जिनमें से अनेक को 'डिजिटल इंडिया' जैसी सरकारी पहल के माध्यम से अधिक सुलभ बनाया गया है। ई–वाहन, एमजीटी–7 कॉर्पोरेट रिटर्न, जीएसटी डेटा और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) जैसे डेटाबेस अब सीधे राष्ट्रीय खातों में योगदान दे रहे हैं। जीएसटी डेटा ने विशेष रूप से त्रैमासिक अनुमानों को और सटीक बनाया है और यह राज्यवार आवंटन में सुधार करेगा । इसका परिणाम अधिक मजबूत और आंतरिक रूप से संगत जीडीपी अनुमान प्रणाली के रूप में सामने आया है। यह संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है, जिसमें जीडीपी अनुमानों की सटीकता बढ़ाने के लिए प्रशासनिक डेटा का नए तरीकों से उपयोग किया जा रहा है।

केवल जीडीपी के लिए ही नहीं, बल्कि मंत्रालय देशभर में साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रशासनिक डेटा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु वातावरण तैयार करने के व्यापक लक्ष्य को भी आगे बढ़ा रहा है। इसके मुख्य प्रयास राज्यों के साथ करीबी तालमेल सहित डेटा की गुणवत्ता, तुलनीयता और अंत: क्रियाशीलता को सुधारने पर केंद्रित हैं, ताकि राष्ट्रीय और उप–राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर डेटा का सुसंगत और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

डेटा–आधारित निर्णय लेने के इस दौर में, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को समझने और लक्षित नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए उप–राष्ट्रीय डेटा बेहद महत्वपूर्ण है। इसी कारण राज्यों और जिलों के स्तर पर जीडीपी के ठोस अनुमान पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है,जिसके लिए राज्यों को तकनीकी सहायता पहले ही प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा, वर्तमान नमूना सर्वेक्षणों में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जिला–स्तरीय अनुमान तैयार किए जा सकें । एएसयूएसई और पीएलएफएस के तहत ये मजबूत उप–राज्य स्तरीय सर्वेक्षण अनुमान उप–राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था का अधिक विस्तृत और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हुए राज्यों/उप–राज्य जीडीपी माप की सटीकता को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे।

आधार वर्ष संशोधन ने कई सुधार लाकर और हमारी सांख्यिकीय प्रणाली की नींव को मजबूती प्रदान करते हुए आवश्यक आधार तैयार किया है। इसके बावजूद, यह केवल एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत है, क्योंकि यह प्रणाली नए सांख्यिकीय उत्पादों और प्रशासनिक डेटा सेट्स के सामंजस्?य जैसी आगामी पहलों के माध्यम से विकसित हो रही है। ये सभी प्रयास मिलकर नीति निर्माताओं को समय पर, विश्वसनीय और क्रियान्वयन योग्य जानकारी प्रदान कर गतिशील, उत्तरदायी और भविष्योन्मुख सांख्यिकीय प्रणाली के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं।

(सौरभ गर्ग, सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हैं। व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं।)

पंजाब सरकार 'रंगला पंजाब' के सपने को साकार करने के लिए सेवा और विकास के प्रति दृढ़ संकल्पित–गुलाब चंद कटारिया

881 आम आदमी क्लीनिकों में मुफ्त दवाइयाँ और टेस्ट; ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या 4.7 करोड़ दर्ज – गुलाब चंद कटारिया

एस के सक्सेना
मनदीप कौर

चंडीगढ़, 6 मार्च–पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज राज्य सरकार की पंजाब और पंजाबियों के प्रति समर्पित भावना और ईमानदारी से सेवा करने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पंजाब सरकार एक गतिशील और प्रगतिशील 'रंगला पंजाब' के निर्माण के उद्देश्य से राज्य को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए समर्पित भावना के साथ कार्य कर रही है।

16वीं पंजाब विधानसभा के बारहवें बजट सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे, शासन व्यवस्था, जनकल्याण, उद्योग और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में पंजाब सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पंजाब सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा,

पंजाब सरकार एक मजबूत, समग्र और जन–केंद्रित स्वास्थ्य व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो 23 जिला अस्पतालों, 42 उप–डिवीजनल अस्पतालों, 162 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 523 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 881 आम आदमी क्लीनिकों और 2453 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। यह व्यवस्था राज्य के प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।卐

उन्होंने आगे कहा,

卐पंजाब भर में 881 आम आदमी क्लीनिकों में 107 प्रकार की दवाइयाँ और 47 प्रकार के टेस्ट मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक ओपीडी में 4.7 करोड़ से अधिक लोग इन सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं, जिनमें 1.55 करोड़ गंभीर बीमारियों के मरीज शामिल हैं। वर्ष 2025–26 में यह संख्या दो करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 240 नए आम आदमी क्लीनिक जल्द ही शुरू किए जाएंगे।卐

राज्यपाल ने कहा,

卐पंजाब में आम आदमी क्लीनिकों में शुरू की गई मातृ एवं शिशु देखभाल सेवाओं ने मातृ मृत्यु दर को 105 से घटाकर 90 करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो सुरक्षित मातृत्व के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा, इन क्लीनिकों में रेबीज विरोधी टीकाकरण सेवाएं भी शुरू की गई हैं।卐

स्वास्थ्य कर्मियों की मजबूती पर जोर देते हुए राज्यपाल ने कहा,

卐पंजाब सरकार ने इतिहास में डॉक्टरों की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती की है। वर्ष 2022 से अब तक सरकारी अस्पतालों के लिए 934 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, जो वर्तमान में राज्य में कार्यरत कुल डॉक्टरों का लगभग 25 प्रतिशत है।卐

उन्होंने आगे कहा,

卐पंजाब सरकार लगभग 400 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती और सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, जो विशेषज्ञ सेवाओं के सबसे बड़े विस्तार को दर्शाता है। इसी प्रकार 400 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि 500 अतिरिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है।卐

व्यापक स्वास्थ्य कवरेज का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा,

卐पंजाब सरकार ने 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना' के तहत राज्य की पूरी आबादी को 100 प्रतिशत स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था लागू की है। इस योजना के तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से 2356 मेडिकल और सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। पंजाब और चंडीगढ़ में ऐसे अस्पतालों की संख्या लगभग 900 है।卐

उन्होंने आगे कहा,

卐इस योजना के तहत प्रत्येक पंजाबी को कैशलेस इलाज के लिए स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा।卐

सड़क सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं के बारे में बोलते हुए राज्यपाल ने कहा,

卐पंजाब सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 'फरिश्ते' और 'सड़क सुरक्षा फोर्स' की शुरुआत की है। 'फरिश्ते' योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है और घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले परोपकारी नागरिकों को 2,000 रुपये और प्रशंसा प्रमाणपत्र भी दिया जाता है। इस पहल के माध्यम से अब तक 600 से अधिक सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर सहायता मिल चुकी है।卐

तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा,

卐पंजाब सरकार ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज को शुरू करके उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की ऐतिहासिक पहल की है। दिसंबर 2025 में पहले सफल लिवर ट्रांसप्लांट के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत लिवर ट्रांसप्लांट सेवाएं औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी हैं।卐

उन्होंने आगे कहा,

卐मई 2026 से सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला और सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर में किडनी ट्रांसप्लांट सेवाएं शुरू करने की योजना है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया मील का पत्थर साबित होगा।卐

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा,

卐'सीएम दी योगशाला' एक अनूठी पहल है, जिसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न शहरों में प्रतिदिन लगभग 5000 प्रशिक्षकों की निगरानी में योग कक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख लोग भाग लेते हैं।卐

नशे की समस्या पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा,

卐पंजाब सरकार ने राज्य में नशे की समस्या और तस्करी से निपटने के लिए 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान शुरू किया है।

उन्होंने आगे बताया कि इस अभियान के तहत नशा मुक्ति सेवाओं को सुलभ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पूरे पंजाब में 548 ओओटी क्लीनिक संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा उपचार और पुनर्वास के लिए 36 सरकारी तथा 177 निजी नशा मुक्ति केंद्र, और 19 सरकारी तथा 74 निजी पुनर्वास केंद्र कार्यरत हैं। कैदियों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए 19 जेलों में भी नशा मुक्ति सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने आगे कहा कि इस महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत से अब तक 10.63 लाख से अधिक मरीजों का पंजीकरण किया गया है और उन्हें नशा मुक्ति तथा पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से उपचार प्रदान किया गया है।

कैंसर रोगियों को दी जा रही सहायता के बारे में जानकारी देते हुए राज्यपाल ने बताया कि पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य है, जहाँ मुख्यमंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना के तहत कैंसर का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 957 करोड़ रुपये की राशि से 74,000 से अधिक कैंसर मरीजों को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

आपदा प्रबंधन के संबंध में उन्होंने बताया कि हाल ही में आई बाढ़ के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक मेडिकल कैंप और विशेष जनस्वास्थ्य अभियान चलाए गए थे। इन अभियानों के अंतर्गत फॉगिंग, आशा वर्करों द्वारा घर–घर पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाएँ देना और दवा किटों का वितरण शामिल था। इसके अतिरिक्त 2300 से अधिक गांवों में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से 8 लाख से अधिक मरीजों की जांच की गई, ताकि संकट की स्थिति में समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें और बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित हो सके।

शिक्षा सुधारों को रेखांकित करते हुए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि पंजाब शिक्षा क्रांति के तहत अप्रैल 2022 से अब तक 13,765 शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है।

उन्होंने आगे कहा कि पांच दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 234 प्रिंसिपलों और शिक्षा अधिकारियों के सात बैचों को सिंगापुर, 199 हेडमास्टरों के चार बैचों को आईआईएम अहमदाबाद तथा 144 प्राथमिक कैडर शिक्षकों के दो बैचों को तुर्कू (फिनलैंड) प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।

उन्होंने बताया कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे–2024 में पंजाब एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। स्कूलों में सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 160 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 118 सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' के रूप में विकसित किया जा रहा है।

सिंचाई और कृषि के विषय में जानकारी देते हुए राज्यपाल ने कहा कि सभी किसानों तक नहरी पानी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार ने लगभग 787 करोड़ रुपये के निवेश से 3,443 किलोमीटर नए खालों और भूमिगत पाइपलाइनों के निर्माण की योजना बनाई है। इनमें से 2,650 किलोमीटर कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

उन्होंने आगे बताया कि पंजाब सरकार ने 4,557 करोड़ रुपये की लागत से 2,600 किलोमीटर नहरों की लाइनिंग का कार्य पूरा कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप पहली बार लगभग 1,365 स्थानों तक नहरी पानी पहुंच सका है, जिनमें से 465 स्थानों तक वर्ष 2025 में पानी पहुंचाया गया। लंबे समय से लंबित सरहिंद फीडर नहर की रीलाइनिंग परियोजना भी अब पूरी हो चुकी है।

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आगे बताया कि कंडी क्षेत्र के अर्ध–पर्वतीय इलाकों को पहली बार नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए पंजाब सरकार ने 28 नई लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की पहचान की है, जिनमें से 15 योजनाएँ पहले ही शुरू की जा चुकी हैं।

किसानों को दी जा रही सहायता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2025–26 के दौरान पंजाब सरकार ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना द्वारा अनुशंसित बीटी कॉटन हाइब्रिड बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त खरीफ (सावनी) मौसम में मक्का के रकबे को बढ़ाने के लिए पठानकोट, गुरदासपुर, बठिंडा, संगरूर, जालंधर और कपूरथला जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत किसानों को प्रति एकड़ 17,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

उन्होंने आगे बताया कि पंजाब सरकार ने इस वर्ष गन्ने के मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 15 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। आगामी पेराई सत्र के लिए राज्य सरकार 416 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का मूल्य दे रही है, जो देश में गन्ना किसानों को दी जाने वाली सबसे अधिक कीमत है।

राज्यपाल ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को 33.96 करोड़ रुपये मूल्य का 84,889.7 क्विंटल गेहूं का बीज और 65.15 लाख रुपये मूल्य का 620.5 क्विंटल सरसों का बीज नि:शुल्क वितरित किया है। इसके अतिरिक्त किसानों को मुफ्त बिजली सुविधा देने के लिए वर्ष 2025–26 में 9,992 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि पंजाब में बागवानी के टिकाऊ विकास के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से 1,300 करोड़ रुपये का परियोजना प्रगति पर है, जो क्लस्टर स्तर पर एकीकृत मूल्य श्रृंखला की स्थापना और बदलते जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप बागवानी फसलों को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने कहा कि पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा 12,597 करोड़ रुपये की कुल लागत से 40,103 किलोमीटर टूटी या क्षतिग्रस्त लिंक सड़कों के उन्नयन और आधुनिकीकरण की परियोजना चल रही है।

उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड ने 350.25 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य रखा है और 12 दिसंबर 2025 तक 220.54 करोड़ रुपये की वसूली भी कर ली गई है।

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि वर्ष 2025–26 में रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग ने 959 प्लेसमेंट कैंपों और रोजगार मेलों के माध्यम से 48,912 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं।

खेलों के विकास के बारे में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने वर्ष 2025–26 में खेलों के लिए 362.24 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। खेल विभाग द्वारा 10,406 खिलाड़ियों को खेल उपकरणों की खरीद के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 12.15 करोड़ रुपये, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने वाली खिलाड़ियों और उनके कोचों को 4.91 करोड़ रुपये, तथा अप्रैल 2023 से मार्च 2025 के बीच राष्ट्रीय चैंपियनशिप, अंतर–विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं और जूनियर–सीनियर प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 1060 खिलाड़ियों को 23.1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

उन्होंने बताया कि महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, पटियाला के लिए वर्ष 2025–26 में 15 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है तथा पंजाब भर में 3,100 खेल मैदानों के विकास के लिए 190 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

निवेश और औद्योगिक विकास पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 8,261 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें लगभग 1,50,817 करोड़ रुपये के निवेश और करीब 5,31,619 लोगों के लिए रोजगार की संभावना है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी के विदेशी कारोबारियों के साथ–साथ देश के विभिन्न राज्यों के कारोबारियों से सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है। 'उद्योग क्रांति पहल' के हिस्से के रूप में पंजाब सरकार ने 2025 में 24 सेक्टोरल कमेटियों का गठन भी किया है।

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने यह भी कहा कि जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग ने हाल ही में 606 गांवों को कवर करने वाले 15 बड़े सतही जल परियोजनाओं में से सात को चालू किया है, जिनकी लागत 519.88 करोड़ रुपये है। इससे 7.37 लाख आबादी को लाभ होगा और सभी 15 परियोजनाएं पूरी होने पर लगभग 25 लाख आबादी को लाभ पहुंचेगा।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने दिसंबर 2025 तक के बकाए सहित सभी बिजली सब्सिडी बकाए सफलतापूर्वक निपटा दिए हैं। पंजाब बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड मजबूत जनता निगरानी के साथ निजी निवेश और विशेषज्ञता को एकीकृत करते हुए सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है।

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि फरवरी 2024 से जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा फोर्स ने 43,983 सड़क हादसों के मामलों से निपटते हुए कुल 47,386 लोगों की मदद की। उन्होंने कहा कि इस दौरान लगभग 19,973 व्यक्तियों को मौके पर प्राथमिक सहायता प्रदान की गई, जबकि 27,413 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जो तत्काल आपातकालीन प्रतिक्रिया के माध्यम से कीमती जानें बचाने में फोर्स के योगदान को दर्शाता है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान 500 अतिरिक्त वाहनों की खरीद के लिए ईआरएसएस डायल–112 वाहनों की खरीद हेतु 50 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आयोजनों के बारे में बात करते हुए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पुरब को श्रद्धा के साथ मनाने के लिए अक्टूबर–नवंबर 2025 के दौरान श्रृंखलाबद्ध आयोजन करवाए गए। उन्होंने कहा कि पंजाब भर में नगर कीर्तन सजाए गए, जिनकी समाप्ति श्री आनंदपुर साहिब में हुई और श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित विधान सभा का विशेष सत्र 24 नवंबर 2025 को श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित किया गया, जहां विधान सभा द्वारा गुरु साहिब की महान कुर्बानी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

उन्होंने आगे कहा कि आदमपुर में 140 करोड़ रुपये की लागत से नया हवाई टर्मिनल पूरा हो गया है और भारतीय वायु सेना स्टेशन हलवारा में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की अनुमति मिलने के बाद 161 एकड़ जमीन प्राप्त की गई है, जिसमें से 135.54 एकड़ पर हवाई अड्डा बनाया जाना है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने अंतरिम टर्मिनल इमारत को पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपये जारी किए हैं और जल्द ही उड़ानें शुरू करने के लिए सड़क संपर्क के लिए अतिरिक्त फंड जारी किए गए हैं।

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पंजाब विधान सभा ने इस हवाई अड्डे का नाम शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है।

प्रशासनिक सुधारों और पारदर्शिता के बारे में बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक विजिलेंस ब्यूरो ने 20 गजेटेड अधिकारियों, 134 नॉन–गजेटेड कर्मचारियों और 44 निजी व्यक्तियों के खिलाफ 135 ट्रैप केस दर्ज किए हैं, जिन्हें अवैध रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था।

उन्होंने आगे कहा कि विजिलेंस ब्यूरो ने 23 मार्च 2022 को भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन नंबर 95012–00200 शुरू किया और इस नंबर पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर 63 केस दर्ज किए गए हैं।

राज्यपाल ने यह भी कहा कि जीएसटी संग्रह में लगातार वृद्धि हो रही है और पंजाब ने अप्रैल–अक्टूबर 2025–26 के दौरान पिछले साल के 13,550.62 करोड़ रुपये की तुलना में 15,494.03 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं, जो 1,943.41 करोड़ रुपये या 14.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने व्यापारी समुदाय को राहत प्रदान करने और लंबे समय से लंबित मुकदमेबाजी के समाधान के लिए 1 अक्टूबर 2025 से एकमुश्त निपटारा योजना 2025 अधिसूचित की है।

राज्यपाल ने कहा कि पंजाब भर में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार ने 2025–26 के दौरान रंगला पंजाब विकास योजना शुरू की है, जिसके तहत सभी 117 विधान सभा क्षेत्रों में स्थानीय बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण या अपग्रेड किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब ने भारत का पहला डिजिटली आधारित बाढ़ राहत प्रणाली शुरू की है, जो तेज सर्वेक्षण और मुआवजे के सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर सुनिश्चित करते हुए हजारों बाढ़ प्रभावित परिवारों को बिना किसी देरी या दलाली के तत्काल सहायता प्रदान करने में सक्षम है।

प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब ने आरटीए और आरटीओ कार्यालयों में जनता काउंटरों पर लोगों की लंबी लाइनों की प्रथा समाप्त कर सभी 56 परिवहन सेवाओं को सेवा केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया है, जिससे नागरिक–केंद्रित सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान हो गई है। उन्होंने कहा कि सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी कार्यक्रम के तहत सेवाओं की संख्या 43 से बढ़ाकर 412 कर दी गई है।

राज्यपाल ने कहा कि खरीफ मंडीकरण सीजन 2025–26 के दौरान सरकारी खरीद एजेंसियों ने 156.11 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और 37,294.68 करोड़ रुपये की एमएसपी राशि लगभग 7.38 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की।

उन्होंने आगे कहा कि रबी मंडीकरण सीजन 2025–26 के दौरान 116.17 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया और 28,171.23 करोड़ रुपये की एमएसपी राशि 7.30 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई। इसके साथ पंजाब ने केंद्रीय पूल में लगभग 40 प्रतिशत गेहूं का योगदान दिया।

उन्होंने कहा कि लगभग 40 लाख परिवार और 1.52 करोड़ लाभार्थी खाद्य वितरण प्रणाली के तहत पंजीकृत हैं और पंजाब सरकार के खाद्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त गेहूं के लिए योग्य परिवारों को हर तिमाही 2 किलो दाल, 2 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 लीटर तेल और 200 ग्राम हल्दी भी मिलेगी।

राज्यपाल ने आगे कहा कि 31 दिसंबर 2025 तक मुफ्त बस यात्रा योजना के तहत महिलाओं ने लगभग 60 करोड़ रुपये के खर्च के साथ मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ लिया है।

डिजिटल शासन सुधारों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने ईजी जमाबंदी पहल शुरू की है, जिससे नागरिक व्हाट्सएप के माध्यम से जमाबंदी की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य के नागरिक इंतकाल सेवाएं, रपट एंट्री और जमीन से संबंधित अन्य सेवाएं ऑनलाइन पोर्टलों या घर बैठे सेवा सहायकों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि ईजी रजिस्ट्री प्रोजेक्ट पंजाब भर में लागू किया गया है, जो सरल डीड फॉर्मेटों और डिजिटल संचार के माध्यम से पारदर्शी संपत्ति पंजीकरण सुनिश्चित करता है।

राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई है और पंजाब सरकार ने हर साल 7.50 लाख नागरिकों को तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है।

उन्होंने आगे कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लुधियाना में 809.26 करोड़ रुपये की लागत वाले 75 प्रोजेक्ट, अमृतसर में 686.51 करोड़ रुपये की लागत वाले 41 प्रोजेक्ट, जालंधर में 722.88 करोड़ रुपये की लागत वाले 58 प्रोजेक्ट और सुल्तानपुर लोधी में 33.77 करोड़ रुपये की लागत वाले आठ प्रोजेक्ट पूर्ण किए गए हैं।

राज्यपाल ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों के लिए कई कल्याण योजनाएं लागू कर रही है, जिसमें अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम शामिल है। इसके तहत 2025–26 में 2.70 लाख छात्रों के लक्ष्य के मुकाबले 1.65 लाख छात्रों को 195.99 करोड़ रुपये की राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है।

उन्होंने आगे कहा कि आशीर्वाद स्कीम के तहत 47,588 परिवारों को लाभ पहुंचाते हुए 242.70 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जबकि पंजाब अनुसूचित जातियां भूमि विकास और वित्त निगम ने 322 लाभार्थियों को 6.85 करोड़ रुपये और पंजाब पिछड़ी श्रेणियां भूमि विकास और वित्त निगम ने स्वरोजगार योजनाओं के तहत 286 लाभार्थियों को 9.28 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

राज्यपाल ने आगे कहा कि अमृतसर, बठिंडा, फरीदकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, लालडू, लुधियाना, पटियाला, जालंधर, नंगल और रूपनगर में 11 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया गया है।

बिजली क्षेत्र में विभिन्न सुधारों को उजागर करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पंजाब सरकार 'रौशन पंजाब' पहल के तहत ग्रिड बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि पछवाड़ा से प्राप्त होने वाले अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले ने थर्मल प्लांटों के संचालन में सुधार किया है, जिसके परिणामस्वरूप कोल इंडिया लिमिटेड के कोयले की तुलना में लगभग 380 करोड़ रुपये की बचत हुई है और पीएसपीसीएल थर्मल पावर स्टेशनों को अब कोयले की कोई कमी नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने जुलाई 2022 से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली योजना लागू की है, जिससे लगभग 90 प्रतिशत परिवारों को दो महीने के बिल साइकिल में जीरो बिल आ रहा है। इसके साथ ही सभी कृषि उपभोक्ताओं को निर्विघ्न मुफ्त बिजली दी जा रही है और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 5.837 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी दर पर बिजली प्रदान की जा रही है।

अपने भाषण का समापन करते हुए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने दोहराया कि पंजाब सरकार पारदर्शी शासन, सर्वांगीण विकास और लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा गतिशील एवं प्रगतिशील 'रंगला पंजाब' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राज्य भर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे, उद्योग और नागरिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

भगवंत मान सरकार द्वारा पंजाब के विकास में तेजी लाने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रगतिशील औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 लॉन्च

नीति के तहत निवेशक-संचालित प्रोत्साहन ढांचे के साथ स्थिर पूंजी निवेश पर 100 प्रतिशत तक के प्रोत्साहन की पेशकश, नई नीति के तहत भारत और दुनिया भर के निवेशकों को पंजाब में कारोबार करने का खुला निमंत्रण-संजीव अरोड़ा

कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा

चंडीगढ़, 7 मार्च-औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 की शुरुआत के साथ पंजाब ने आज अपने औद्योगिक विकास के मार्ग को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया है, जो पूरे पंजाब में औद्योगिक विस्तार में तेजी लाने, बड़े निवेशों को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से रचा गया व्यापक ढांचा है। इस नीति का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लुधियाना में उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली और स्थानीय निकाय मंत्री संजीव अरोड़ा की मौजूदगी में किया।

इस समारोह में लगभग 200 प्रमुख उद्योगपतियों और कई क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो पंजाब के औद्योगिक भविष्य में मजबूत औद्योगिक रुचि और विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है।

नीति को देश की सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नीति ढांचों में से एक बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह मिसाली पहल निर्माण, सेवाओं और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए एक अग्रणी स्थान के रूप में पंजाब की स्थिति को और मजबूत करेगी। औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 पंजाब को भारत में सबसे आकर्षक निवेश स्थानों में से एक बनाने के उद्देश्य से प्रोत्साहन और सुधारों की एक विस्तृत

श्रृंखला पेश करती है।

नीति के मुख्य बिंदु-

विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक साथ घोषित 24 क्षेत्र-विशेष नीतियों वाली व्यापक औद्योगिक नीति।

निवेशक अपनी निवेश योजनाओं के अनुसार 20 विभिन्न प्रोत्साहनों में से अपने लिए लाभदायक प्रोत्साहन पैकेज चुनने की स्वतंत्रता। पंजाब में योग्य उद्योगों के लिए पहली बार पूंजी सब्सिडी शुरू की गई। नीति के तहत कई प्रोत्साहनों के संयोजन से स्थिर पूंजी निवेश (स्नष्टढ्ढ) पर 100 प्रतिशत तक के प्रोत्साहन उपलब्ध। आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाओं को नीतिगत ढांचे के तहत प्रोत्साहनों के लिए योग्य बनाया गया।

रोजगार सृजन सब्सिडी की योग्यता को घटाकर 25 करोड़ रुपये निवेश और 50 श्रमिकों तक कर दिया गया, जिससे बड़ी संख्या में उद्योगों के लिए प्रोत्साहन पहुंच योग्य हो गए। महिलाओं, एससी/एसटी, दिव्यांगजनों, आईटी/आईटीईएस और जीसीसी क्षेत्रों के लिए उच्च रोजगार प्रोत्साहन।

सीमावर्ती और किनारे वाले क्षेत्रों में स्थित 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और उद्योगों के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन।

स्टार्टअप सीड ग्रांटों में वृद्धि और मोहाली में एक सरकारी स्टार्टअप हब की स्थापना से स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना।

आईटी/आईटीईएस और जीसीसी, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं निर्माण (श्वस्ष्ठरू), सेमीकंडक्टर, फिल्म निर्माण और पर्यटन क्षेत्रों के लिए समर्पित नीतियां पेश की गईं।

? प्रोत्साहन के लिए स्थिर पूंजी निवेश गणना में जमीन, श्रम आवास, अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं, ईटीपी/एसटीपी/जेडएलडी और पर्यावरणीय बुनियादी ढांचा शामिल।

पंजाब से निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए माल और मार्केटिंग सब्सिडी सहायता पेश की गई।

मेगा निवेश परियोजनाओं की सुविधा के लिए एक अनुकूलित पैकेज समिति स्थापित की गई।

दीर्घकालिक नीति स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निवेशकों को 15 वर्षों तक की बढ़ाई गई प्रोत्साहन अवधि का विकल्प दिया गया। पंजाब में कारोबार करने की सुगमता को और बेहतर बनाने के लिए बिजली आपूर्ति, श्रम नियमों और भवन अनुमतियों में बड़े सुधार। इस अवसर पर बोलते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा, 卐यह नीति भारत और दुनिया भर के निवेशकों को एक स्पष्ट संदेश देती है- पंजाब कारोबार के लिए खुला है। देश के सबसे व्यापक प्रोत्साहन ढांचे के साथ, हम उद्योग के विकास, निवेश और रोजगार सृजन के लिए सही पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं।卐

नए ढांचे में दिये जा रहे लचीलेपन के बारे में बताते हुए मंत्री संजीव अरोड़ा ने आगे कहा, 卐यह पहली बार हुआ है जब किसी नीति के तहत निवेशकों को इतनी खुली और शक्ति दी गई है। निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार वह प्रोत्साहन चुन सकते हैं जो वे चाहते हैं और साथ ही उन्हें वह समय अवधि चुनने की आजादी है जो उनके लिए अधिक लाभदायक हो। यह लचीलापन और निवेशक-आधारित ढांचा बेमिसाल है और भारत में सबसे अधिक निवेशक-अनुकूल राज्य बनने के लिए पंजाब की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।卐

पंजाब सरकार ने दोहराया कि औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति 2026 औद्योगिक विकास को तेज करने, पंजाब की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने और पंजाब के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सरकार ने घरेलू और वैश्विक निवेशकों को पंजाब में संभावनाओं की खोज करने और प्लाक्षा यूनिवर्सिटी मोहाली में 13-15 मार्च, 2026 को होने जा रहे प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन-2026 में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया।

हरियाणा में 'भू-मित्र' व्हाट्सऐप चैटबॉट लॉन्च, भूमि व राजस्व सेवाएँ होंगी 24 ×7 उपलब्ध

भूमि व राजस्व सेवाएँ अब हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध

मनदीप कौर

चंडीगढ़- हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 'भू-मित्र' नामक व्हाट्सऐप आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है, जो भूमि और राजस्व से संबंधित सेवाएँ लेने वाले नागरिकों को 24म7 सहायता प्रदान करेगा। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध यह चैटबॉट राज्य के हर नागरिक के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि भू-मित्र एक स्मार्ट, संवादात्मक (कन्वर्सेशनल) चैटबॉट है, जिसे सीधे व्हाट्सऐप के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म पहले से ही हरियाणा के नागरिकों के बीच व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अब नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने या जटिल पोर्टलों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने स्मार्टफोन पर कुछ ही क्लिक के माध्यम से घर बैठे दिन के किसी भी समय आवश्यक राजस्व सेवाएँ प्राप्त कर सकेंगे। डॉ. मिश्रा ने आगे बताया कि भू-मित्र चैटबॉट के माध्यम से नागरिक फिलहाल चार प्रमुख राजस्व सेवाओं का लाभ ले सकते हैं भूमि स्वामित्व और खेती संबंधी रिकॉर्ड के लिए जमाबंदी की प्रति, भूमि स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित इंतकाल (म्यूटेशन) की प्रति, संबंधित मामलों के लिए मुआवजा पंजीकरण तथा दस्तावेज़ पंजीकरण (डीड रजिस्ट्रेशन) से संबंधित सहायता। इसके अतिरिक्त चैटबॉट के माध्यम से डीड टोकन जनरेशन, भूमि सीमांकन के लिए आवेदन, भूमि एवं राजस्व से जुड़ी शिकायत दर्ज करना, तथा शिकायत की स्थिति की रियल-टाइम ट्रैकिंग जैसी सुविधाएँ भी एक सरल संवादात्मक इंटरफेस के जरिए व्हाट्सऐप पर उपलब्ध होंगी। नागरिक व्हाट्सऐप नंबर 95933 00009 को सेव करके और उस पर मैसेज भेजकर भू-मित्र सेवा का उपयोग कर सकते हैं। यह चैटबॉट साल के 365 दिन, चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा और हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में सहज संवाद की सुविधा प्रदान करेगा।

खेल मंत्री गौरव गौतम के प्रयासों से पलवल नगर परिषद को मिली बड़ी सौगात

पंकज

चंडीगढ़-हरियाणा के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा कैबिनेट की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस प्रस्ताव के तहत प्रांतीय सरकार की भूमि को नगर परिषद पलवल को पार्किंग स्थल तथा नगर परिषद के ऑफिसर-कम-कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए वर्तमान कलेक्टर रेट की दरों पर ट्रांसफर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पलवल शहर की लंबे समय से चली आ रही पार्किंग समस्या एवं नगर परिषद के लिए उपयुक्त प्रशासनिक परिसर की आवश्यकता को लगातार सरकार के समक्ष उठाया था।

पंजाब पुलिस ने 581 स्थानों पर छापेमारी की; 186 गिरफ्तार

पुलिस टीमों ने 82 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की, 73 को पूछताछ के बाद रिहा किया

रमन कुमार

चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई फैंसलकुन्न 'गैंगस्टरों ते वार' मुहिम के 53वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में गैंगस्टरों के साथियों की पहचान की गई और मैप किए गए 581 स्थानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि 卐गैंगस्टरों ते वार卐 पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए फैंसलकुन्न जंग है, जिसे 20 जनवरी, 2026 को पुलिस निदेशक जनरल (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने शुरू किया था। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के तालमेल में सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष कार्रवाइयां कर रही हैं। 53वें दिन, पुलिस टीमों ने 186 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1 हथियार बरामद किया, जिससे मुहिम की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 14,526 हो गई है। इसके अलावा, 82 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 73 व्यक्तियों को पूछताछ और जांच के बाद रिहा किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 2 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। जनता एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से आवश्यक अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में जानकारी साझा कर सकती है, तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना दे सकती है। इस दौरान पुलिस टीमों ने नशे के खिलाफ अपनी मुहिम 卐युद्ध नशों विरुद्ध 卐 को 378वें दिन भी जारी रखते हुए आज 92 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 526 ग्राम हेरोइन, 515 नशीली गोलियाँ/कैप्सूल और 9540 रुपये ड्रग मनी बरामद किए। इससे केवल 378 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की संख्या 53,562 हो गई है। नशा छुड़ाने की मुहिम के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज 35 व्यक्तियों को नशा छुड़वाने और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए राजी किया।

खेतों से जल सुरक्षा तक-भारत-इज़राइल सहयोग कैसे नागरिकों तक पहुँचता है

भारत-इज़राइल संबंधों की चर्चा अक्सर कूटनीति के संदर्भ में होती है। लेकिन इन्हें समझने का अधिक स्पष्ट तरीका यह है कि सहयोग के ठोस परिणामों को देखा जाए-यह किसानों, शहरों, स्टार्टअप्स और सुरक्षा संस्थानों तक क्या वास्तविक लाभ पहुँचाता है।

सबसे पहले कृषि क्षेत्र की बात करें, जहाँ परिणाम जमीन पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। भारत और इज़राइल मिलकर *इंडो-इज़राइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट* चला रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान और तकनीक का आदान-प्रदान तथा प्रदर्शन आधारित प्रशिक्षण है। इस परियोजना का प्रमुख हिस्सा *सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (ष्टद्गठ्ठह्लह्म्द्गह्य शद्घ श्व×ष्द्गद्यद्यद्गठ्ठष्द्ग)* का एक नेटवर्क है-ऐसे उन्नत कृषि केंद्र जहाँ इज़राइली कृषि तकनीकों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करके प्रदर्शित किया जाता है। भारत सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, देश के 12 राज्यों में *29 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस* संचालित हैं, जो इसे भारत के सबसे संरचित सरकार-से-सरकार (त्र2त्र) कृषि सहयोग मॉडलों में से एक बनाता है।

Dr M. Chuba
National Vice President of the Bharatiya Janata Party (BJP).

ये केंद्र व्यावहारिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करते हैं। यहाँ तकनीक को केवल 卐आयात卐 के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उसके *स्थानीय अपनाने (adoption)* पर ध्यान दिया जाता है-जैसे फसल-विशिष्ट सर्वोत्तम कृषि पद्धतियाँ, संरक्षित खेती (protected cultivation) की तकनीकें और जल-संचयन व कुशल सिंचाई प्रणालियाँ। विचार सरल है-जब किसान अपनी ही मिट्टी और जलवायु में नई तकनीक को सफल होते हुए देखते हैं, तो उसे अपनाने का भरोसा बढ़ता है और जोखिम कम महसूस होता है।

दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र *जल सुरक्षा* है। भारत में जल संकट केवल ग्रामीण समस्या नहीं है; यह शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में भी चुनौती बन चुका है। इसी कारण भारत-इज़राइल सहयोग में जल प्रबंधन के कई उपाय शामिल हैं-जैसे जल का कुशल उपयोग, माइक्रो-इरिगेशन, तथा विशेष रूप से *अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग (wastewater recycling)* तथा *डिसेलिनेशन (समुद्री जल को पेयजल में बदलना)*। ये केवल नीतिगत

घोषणाएँ नहीं हैं, बल्कि आधिकारिक द्विपक्षीय ढाँचों में शामिल सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं।

व्यावहारिक रूप से देखें तो डिसेलिनेशन और जल पुनर्चक्रण तटीय और तेजी से बढ़ते शहरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जहाँ गर्मियों या पीक डिमांड के समय जल आपूर्ति पर दबाव बढ़ जाता है। *टाइम्स ऑफ इंडिया* की एक रिपोर्ट के अनुसार, विशाखापट्टनम (विज़ाग) में *100 एमएलडी क्षमता वाला डिसेलिनेशन प्लांट* प्रस्तावित है, जिसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें इज़राइल की कंपनी *आईडीई टेक्नोलॉजीज़* तकनीकी भागीदार के रूप में शामिल है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उद्योगों के लिए अलग जल आपूर्ति व्यवस्था करने से पीने के पानी के वितरण पर दबाव कम किया जा सकता है-जिसका सीधा लाभ आम नागरिकों और घरों को मिलता है।

तीसरा स्तंभ है *नवाचार और तकनीकी सहयोग, क्योंकि तकनीकी साझेदारी तब सबसे अधिक लाभ देती है जब वह रोजगार और उद्योग में विस्तार का आधार बनती है। भारत और इज़राइल ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास (क्र×ष्ठ) के लिए **इंडिया-इज़राइल इंडस्ट्रियल आरएंडडी एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड (द्ब4स्न)* स्थापित किया है। आधिकारिक कार्यक्रम स्रोतों के अनुसार यह भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इज़राइल इनोवेशन अथॉरिटी के बीच एक संयुक्त पहल है। इस फंड को सामान्यतः *40 मिलियन डॉलर के बहुवर्षीय कार्यक्रम* के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसका उद्देश्य संयुक्त अनुसंधान, तकनीकी विकास और व्यावसायिककरण को बढ़ावा देना है।

स्टार्टअप्स और उद्योगों के लिए केवल घोषणाएँ नहीं, बल्कि *व्यवहारिक तंत्र (द्वद्गष्द्धड्डठ्ठद्बह्यद्वह्य)* भी महत्वपूर्ण होते हैं। भारत की ओर से *टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड (अष्ठक्च)* संयुक्त परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है और उनकी प्रक्रिया को समर्थन देता है। इससे साझेदार खोजने से लेकर आवेदन, पायलट परियोजनाओं और व्यावसायिक विस्तार तक एक स्पष्ट मार्ग बनता है-जिससे सहयोग केवल सम्मेलनों या प्रतिनिधिमंडलों तक सीमित नहीं रहता।

अंतिम क्षेत्र है *सुरक्षा और रक्षा सहयोग, जिसका नागरिकों पर प्रभाव प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण होता है-बेहतर तैयारी, बेहतर प्रणालियाँ और अधिक सक्षम संस्थान। **बराक-8 / रूक्र-स्रूरू* जैसे सह-विकास कार्यक्रम संयुक्त रक्षा परियोजनाओं के उदाहरण माने जाते हैं। हाल के समय में अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि भारतीय रक्षा निर्माण में साझेदारी से घरेलू क्षमता तेजी से बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर, *फाइनेंशियल टाइम्स* की एक रिपोर्ट में भारत के स्वदेशीकरण अभियान के तहत इज़राइल की *एल्बिट सिस्टम्स* के साथ विकसित एक भारतीय निर्मित *आईएसआर ड्रोन कार्यक्रम* का उल्लेख किया गया है।

इन सभी पहलुओं को साथ रखकर देखें तो यह केवल भू-राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि *व्यावहारिक सहयोग की कहानी* है। किसानों को आधुनिक खेती और सिंचाई तकनीकों तक पहुँच मिलती है। शहरों को जल सुरक्षा के लिए पुनर्चक्रण और डिसेलिनेशन जैसे समाधान मिलते हैं। स्टार्टअप्स को संयुक्त अनुसंधान और नवाचार के लिए संरचित मंच मिलता है। और संस्थानों को रक्षा व सुरक्षा सहयोग के माध्यम से अपनी क्षमता मजबूत करने का अवसर मिलता है।

इसीलिए भारत-इज़राइल संबंधों को समझाने का सबसे सटीक तरीका *जन-केंद्रित दृष्टिकोण* है-इन संबंधों को उस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो नागरिकों के जीवन में प्रत्यक्ष लाभ के रूप में दिखाई देता है, उपयोग में आता है और विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक परिवर्तन लाता है।